● वर्ष-2
● अंक-266
रायपुर, गुरुवार
29 जून 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

समान नागरिक संहिता पर बवाल

प्रधानमंत्री मोदी ने समान नागरिक संहिता लागू करने की वकालत की

शिवेंद्र तिवारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में समान नागरिक संहिता की वकालत करके देश में एक बार फिर इस मुद्दे पर बहस छेड़ दी है। भोपाल में पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। पीएम के इस बयान के बाद सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस समेत कई दलों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं, केंद्र सरकार के मंत्रियों ने समान नागरिक संहिता को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने मंगलवार को भोपाल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस पर विपक्षी दल लोगों को भड़का रहे हैं। एक ही घर में दो कानून कैसे हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी बार-बार कह चुका है कि समान नागरिक संहिता लाओ, लेकिन विपक्षी दल वोट बैंक के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। समान नागरिक संहिताका जिक्र संविधान में भी किया गया है।

समान नागरिक संहिता क्या है?

समान नागरिक संहिता यानी का अर्थ है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों का एक कानून होगा। शादी, तलाक, गोद लेने और जमीन-जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। यह मुद्दा कई दशकों से राजनीतिक बहस के केंद्र में रहा है। ष्टष्ट सत्ताधारी भाजपा के लिए जनसंघ के जमाने से प्राथमिकता वाला एजेंडा रहा है। भाजपा सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता को लागू करने का

वादा करती रही है और यह मुद्दा उसके 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र का भी हिस्सा था।

पक्ष और विपक्ष में बहस

समान नागरिक संहिता लागू होने पर हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून, विशेष विवाह अधिनियम जैसे कानूनों की जगह लेगा। समान नागरिक कानून तब सभी नागरिकों पर लागू होगा चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। इसके समर्थकों का तर्क है कि यह लैंगिक समानता की बढ़ावा देने, धर्म के आधार पर भेदभाव की कम करने और कानूनी प्रणाली की सरल बनाने में मदद करेगा। वहीं, दूसरी ओर विरोधियों का कहना है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा और व्यक्तिगत कानूनों को प्रत्येक धार्मिक समुदाय के विवेक पर छोड़ देना चाहिए।

कई राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठन समान नागरिक संहिता लागू होने का विरोध कर रहे हैं। डीएमके ने कहा कि सभी जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रार्थना करने की अनुमति होनी चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति सहित देश के प्रत्येक व्यक्ति को देश के किसी भी मंदिर में पूजा करने की अनुमति होनी चाहिए। डीएमके के टीकेएस एलंगोवन ने कहा कि हम समान नागरिक संहिता इसलिए नहीं चाहते क्योंकि संविधान ने हर धर्म को सुरक्षा दी है।

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री भारत की विविधता और इसके बहुलवाद को एक समस्या मानते हैं। इसलिए, वह ऐसी बातें कहते हैं... क्या आप समान नागरिक संहिता के नाम पर देश के बहुलवाद और विविधता को छीन लेंगे?... जब वह समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, तो वह हिंदू नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं...मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि क्या वे हिंदू अविभाजित परिवार को खत्म कर सकते हैं?...

केंद्र का रुख

केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मंगलवार को कहा कि देश में समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए ताकि महिलाओं को घरों में वह स्थान मिले जिसकी वे हकदार हैं। उन्होंने कहा, एक देश में दो कानून नहीं हो सकते। इससे पहले, केंद्र ने पिछले साल समान नागरिक संहिता पर उच्चतम न्यायालय में अपने हलफनामे में कहा था कि विभिन्न धर्मों और सम्प्रदायों के लोग अलग-अलग संपत्ति और वैवाहिक कानूनों का पालन करते हैं जो %देश की एकता के खिलाफ% है। अक्टूबर 2022 में एक याचिका के जवाब में दायर हलफनामे में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने कहा था कि अनुच्छेद 44 संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के उद्देश्य को मजबूत करता है।

गैर राजनीतिक विरोध

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मंगलवार देर रात बैठक हुई जो कि करीब तीन घंटे तक चली। ऑनलाइन बैठक में संगठन के पदाधिकारी और अन्य बातों के अलावा विधि आयोग के सामने अपने विचार अधिक मजबूत तरीके से प्रस्तुत करने पर सहमत हुए। बैठक में विधि आयोग को सौंपे जाने वाले दस्तावेजों को भी अंतिम रूप दिया गया।

बोर्ड से जुड़े मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा, बोर्ड समान नागरिक संहिता का पुरजोर विरोध करेगा। हम विधि आयोग के सामने अपनी बात और मजबूती से रखकर सरकार के प्रस्तावित कदम का मुकाबला करने की रणनीति बना रहे हैं। पिछले कई साल से राजनेता चुनाव से ठीक पहले समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाते रहे हैं। इस बार भी यह मुद्दा 2024 चुनाव से पहले सामने आया है। इससे पहले झारखंड में रविवार को 30 से अधिक आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि समान नागरिक संहिता पर चर्चा के लिए एकत्रित हुए। बैठक में फैसला हुआ कि वे विधि आयोग से समान नागरिक संहिता) के विचार को वापस लेने का आग्रह करेंगे।

आदिवासी समन्वय समिति (एएसएस) के बैनर तले इकठ्ठे हुए आदिवासी संगठनों ने इस बात पर गहरा संदेह व्यक्त किया कि समान नागरिक संहिता कई जनजातीय प्रथागत कानूनों और अधिकारों को कमजोर कर सकता है। भारत के 22वें विधि आयोग ने 14 जून को समान नागरिक संहिता पर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों से नए सुझाव मांगे हैं। बैठक में कहा गया कि वे ऐसे किसी भी कानून को अनुमति नहीं देंगे जो आदिवासियों से जमीन छीन ले। साथ ही कहा गया कि हमारे पारंपरिक कानूनों के अनुसार, महिलाओं को शादी के बाद पैतृक भूमि का अधिकार नहीं दिया जाता है।

इन दिनों

✍ अनिल सिन्हा

मणिपुर में ज्यादा खतरनाक है हिंसा

मणिपुर में सुरक्षा बलों की भारी संख्या के बावजूद स्थिति को सामान्य बनाना मुश्किल हो रहा है। मणिपुरी समाज बुरी तरह बंटा दिख रहा है। वहां के दो प्रमुख समुदाय, मैतेई और कुकी एक-दूसरे को जैसे देखने को तैयार नहीं। स्थिति यह है कि मैतेई बहुल इलाकों में रहने वाले कुकी घर-बार छोड़ कर चले गए हैं। यही हाल कुकी बहुल इलाकों में बसे मैतेई लोगों का है। ऐसे में यह सवाल तो है ही कि करीब-करीब गृहयुद्ध में बदल चुकी मणिपुर की हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है? शनिवार को सर्वदलीय बैठक में विपक्ष की एक स्वर से उठी मुख्यमंत्री बदलने की मांग के पीछे भी शायद इसी सवाल की भूमिका है। लेकिन इससे भी गंभीर यह आशंका है कि कहीं यह हिंसा समस्त पूर्वोत्तर को अशांति के एक नए चरण में न धकेल दे। इस आशंका के पीछे कई ठोस कारक हैं, लेकिन पहले मणिपुर की इस हिंसा की पृष्ठभूमि को समझते हैं। वैसे राज्य में हिंसा कोई नई बात नहीं है। यहां समुदायों के बीच संघर्ष का इतिहास पुराना है। 1949 में मणिपुर राज्य के भारत में विलय के साथ ही अलगाववादी प्रवृत्तियां उभरने लगी थीं। सत्तर के दशक में तो हालात इतने बिगड़ गए कि केंद्र सरकार को 1980 आते-आते आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट (अफ्सपा) लागू करना पड़ा। उग्रवादी गतिविधियों के लिए पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों की तरह मणिपुर की भौगोलिक परिस्थितियां भी काफी मददगार रही हैं। जंगल तथा पहाड़ियों के अलावा पड़ोसी म्यांमार के साथ एक खुली सीमा है। दोनों ओर एक ही जनजातियां हैं, जो आपस में सामाजिक-आर्थिक रूप से सदियों से बंधी हैं। संसाधनों की कमी और आधुनिक अर्थव्यवस्था के साथ चलने में असमर्थता के कारण यहां के कुछ समुदाय नशे की खेती और कारोबार में लग गए हैं। नशा, हथियार और उग्रवाद ने मिलकर एक ऐसा खतरनाक मिश्रण तैयार कर दिया है जिससे निपटना सरकार के लिए कठिन हो गया है। लेकिन नशे का कारोबार और उग्रवाद उस गहरी बीमारी के लक्षण भर हैं जिससे पूर्वोत्तर के राज्य ग्रस्त हैं। असल में, यह कबीलाई अस्मिता, संस्कृति और पर्यावरण-संसाधन की रक्षा से जुड़ा सवाल है। स्थानीय कबीलों ने इनकी रक्षा के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद से जमकर लोहा लिया था। दुर्भाग्य से, भारत सरकार ने उपनिवेशवादी नीतियों को पलटने में किसी कल्पनाशीलता का सहारा नहीं लिया और पुराने तरीके ही अमल में लाए। परंपरागत पंचायतें जरूर बहाल हुईं, जनजातीय परिषदों के जरिए उन्हें संसाधनों पर अधिकार और स्वायत्तता भी मिली, लेकिन भारतीय राष्ट्र में इन समूहों को बराबर का भागीदार बनाने का काम अधूरा रह गया। तीन मई की हिंसा हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद भड़की कि राज्य सरकार मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की अनुशंसा करे। कुकी सहित अन्य जनजातियों की ओर से विरोध शुरू हुआ। लेकिन यह जल्दी ही सांप्रदायिक दंगे में बदल गया। हिंसा में 200 से ज्यादा चर्च और 17 मंदिर जलाए गए हैं। इनमें मैतेई ईसाइयों के चर्च भी शामिल हैं। यह समझना जरूरी है कि अब तक उग्रवाद का मुख्य निशाना सुरक्षा बल ही थे।

दिल्ली में हुई छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं की बैठक

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि जनता और कार्यकर्ताओं की सरकार से बड़ी उम्मीदें रहती हैं। हमें खुशी है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जनता और कार्यकर्ताओं दोनों के ही भरोसे पर खरी उतरी है। कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों, कांग्रेस पार्टी की जोड़ने की विचारधारा एवं भाजपा की नकारात्मक सोच के खिलाफ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे।

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं ने बुधवार को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा

की। सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और संगठन की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जानकारी दी। वहीं मंत्रियों ने भी कई सामाजिक और राजनीतिक सुझाव दिए । बैठक के उपरांत छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री टीएस सिंह देव, मंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री शिव कुमार डहरिया, मंत्री कवासी लखमा मौजूद थे।

कुमारी सैलजा ने कहा कि चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से छत्तीसगढ़ नेताओं की चर्चा हुई है। बैठक में छत्तीसगढ़ नेताओं ने अपने सुझाव दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। वहीं संगठन के कार्यक्रमों के बारे में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जानकारी दी। बैठक में सभी ने यही बात कही कि सभी एकजुटता से काम करेंगे। सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे।

सैलजा ने बताया कि बैठक में मल्लिकार्जुन खरगे जी ने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि संविधान कांग्रेस पार्टी के लिए सर्वोपरि है। भाजपा के पास धार्मिक बातों में लोगों को बरगलाने के सिवाय कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस के पास काम और जोड़ने वाली विचारधारा का एजेंडा है। राहुल जी ने कहा कि कांग्रेस को सभी वर्गों को साथ लेकर चलना है। कांग्रेस की विचारधारा देश और समाज को आगे रखती है।सैलजा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अपने साढ़े चार साल के शासन काल में अच्छा काम किया है। प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचा है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जनता के जीवन स्तर में बेहतरी के लिए कार्य किया है। राहुल गांधी जी ने पिछले चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता को न्याय दिलाने की बातें कही थी, उन सब बातों को कांग्रेस सरकार ने लागू किया है। जनता भाजपा और केंद्र सरकार की सच्चाई को जान चुकी है।

प्रमुख समाचार

टीएस सिंह देव को प्रदेश के नए उप-मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव अब छत्तीसगढ़ के नए उप-मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा की गई है। बता दें कि दिल्ली में, ढ्ढष्टष्ट ने

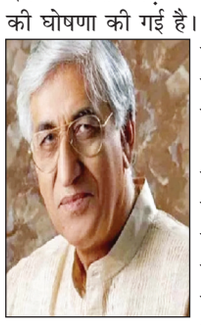

छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव को लेकर अहम बैठक आयोजित की थी।कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव ने कहा कि, सर्वेक्षणों और मीडिया रिपोर्टों से हमें बहुत सकारात्मक रिपोर्ट मिल रही है। हमने जो भी किया है, हम उस पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सीएम चेहरा बदलने का कोई सवाल ही नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पार्टी नेता राहुल गांधी ने आज विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की।

राज्यपाल को दिखाए गए काले झंडे, कांग्रेस ने की निंदा

नईदिल्ली। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को बुधवार को जब उनका काफिला सिलीगुड़ी में उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय (यूएनबी) के परिसर में प्रवेश कर रहा था, तब तृणमूल कांग्रेस

की छात्र शाखा, तृणमूल छात्र परिषद (टीएमसीपी) के सदस्यों ने उन्हें काला झंडा दिखाया। फिलहाल राज्य में यह बड़ा मुद्दा बन गया है। इसको लेकर राजनीति भी जारी है। कांग्रेस ने इसकी निंदा की है। टीएमसीपी का आरोप लगाया कि बोस राजभवन से समानांतर प्रशासन चला रहे थे और इसलिए वे उनकी यात्रा का विरोध कर रहे थे। लगातार तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर रहने वाले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इसकी निंदा की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ममता बनर्जी की सरकार ऐसे निंदनीय कृत्य में लिप्त रही है जो राज्य सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं।

प्रीडेटर ड्रोन सौदे से बढ़ेगी देश की सैन्य क्षमता : वाइस एडमिरल

नईदिल्ली। भारतीय नौसेना के पूर्व उप प्रमुख वाइस एडमिरल एसएन घोरमडे (सेवानिवृत्त) ने भारत-अमेरिका प्रीडेटर ड्रोन सौदे पर बात की है। उन्होंने बताया कि यह सशस्त्र बलों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सौदा है क्योंकि यह खुफिया, निगरानी और टोही क्षमता प्रदान करता है... हम हिंद महासागर क्षेत्र के व्यापक विस्तार और हमारे उत्तरी और पश्चिमी पड़ोसियों के साथ सीमाओं को भी कवर करने में सक्षम हैं। वह आगे कहते हैं कि कीमत तय नहीं की गई है। मुझे लगता है कि कीमत को लेकर अटकलें चल रही हैं, जिसे अलग रखा जाना चाहिए। जो भी किया जाएगा, राष्ट्रीय हित में किया जाएगा। वाइस एडमिरल एसएन घोरमडे ने भारत-अमेरिका प्रीडेटर ड्रोन सौदे पर बात करते हुए कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी गलत काम की कोई गुंजाइश है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसकी हमें जरूरत है। एक प्रक्रिया है जिसका पालन किया जा रहा है जिसके लिए जांच और संतुलन अंतर्निहित हैं।

चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा से नहीं हटा रहा रोक

नईदिल्ली। चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को रोका हुआ है, पिछले कई सालों से स्थगित चल रही कैलाश-मानसरोवर यात्रा के मद्देनजर उत्तराखंड पर्यटन विभाग के अधिकारी इस संबंध

में वैकल्पिक तरीके खोज रहे हैं जिससे श्रद्धालुओं को भगवान शिव के निवास स्थान माने जाने वाले कैलाश पर्वत की झलक भारतीय भूभाग से ही मिल सके। उत्तराखंड पर्यटन के अधिकारियों ने बताया है कि इसके लिए राज्य पर्यटन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में तिब्बत के प्रवेशद्वार लिपुलेख दर्रे के पश्चिमी ओर स्थित पुरानी लिपुलेख चोटी से %कैलाश दर्शन% की संभावनाओं का परीक्षण शुरू कर दिया है। धारचूला के उपजिलाधिकारी देवेश शास्त्री ने बताया, ''हाल में पर्यटन अधिकारियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों, साहसिक पर्यटन विशेषज्ञों और सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों ने पुरानी लिपुलेख चोटी का दौरा किया था।

आदिपुरुष मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को फिल्म आदिपुरुष पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फिल्म निर्माताओं से धार्मिक ग्रंथों से दूर रहने और उनके बारे में फिल्में नहीं बनाने का आग्रह किया। अदालत ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को प्रतिबंध की मांग करने वाली याचिकाओं के जवाब में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान एवं श्रीप्रकाश सिंह ने कहा कि आप लोगों को कुरान, बाइबल को भी नहीं छूना चाहिए। मैं ये क्लियर कर दूं कि किसी एक धर्म को मत छुओ। आप लोग किसी भी धर्म के बारे में गलत तरह से मत दिखाइए। कोर्ट का कोई धर्म नहीं है आपको कुरान या बाइबिल को नहीं छूना चाहिए। मैं स्पष्ट कर दूं कि आपको किसी भी धर्म को नहीं छूना चाहिए। कृपया धर्मों को गलत रोशनी में न दिखाएं। न्यायमूर्ति चौहान ने सुझाव देने से पहले मौखिक रूप से टिप्पणी की कि कुरान पर गलतियों को दर्शाने वाली एक छोटी डॉक्यूमेंट्री भी बड़े पैमाने पर हलचल पैदा करेगी।

जुर्माना बढ़ने का नहीं दिख रहा असर

देश में चार लाख सड़क हादसों में डेढ़ लाख लोगों की मौत

जितेंद्र भारद्वाज

देश में नया मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद यह उम्मीद बंधी थी कि अब सड़क हादसों में कमी आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मौजूदा समय में सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। चार साल पहले लागू हुए नए मोटर वाहन अधिनियम में चालान राशि में कई गुना बढ़ोतरी हुई थी। देश में प्रतिवर्ष चार लाख से ज्यादा सड़क हादसे हो रहे हैं। इन हादसें में रोजाना औसतन 421 लोगों की मौत हो जाती है। अमेरिका में एक साल के दौरान 19 लाख हादसे हुए, लेकिन मौत का आंकड़ा 36560 रहा। सड़क हादसों में मारे जाने वाले लोगों की संख्या के मामले में भारत ने कई विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, भारत में 2021 के दौरान हुए 412432 सड़क हादसों में 153972 लोग मारे गए, जबकि 384448 लोग घायल हुए थे। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, कद्दावर नेता राजेश पायलट, केंद्रीय मंत्री रहे गोपीनाथ मुंडे और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा से लेकर टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन सायरस मिस्त्री तक अनेक लोग सड़क हादसों का शिकार हुए हैं। देश में सितंबर 2019 से लागू हुए नए मोटर वाहन अधिनियम में चालान राशि में कई गुना इजाफा किया गया। इसके बाद उम्मीद बंधी थी कि अब वाहन चालक संभल कर चलेंगे और सड़क हादसों में कमी आ जाएगी, लेकिन

ऐसा कुछ नहीं हुआ।

सड़क सुरक्षा पर काम कर रहे %सेव लाइफ फाउंडेशन% के अध्यक्ष पीयूष तिवारी कहते हैं, सड़क हादसे होने की कई वजह होती हैं। इसमें यह पॉइंट भी बहुत अहम है कि देश में यातायात के नियमों को लेकर लोगों का व्यवहार क्या है। रिसर्च बताती है कि सड़क हादसे के लिए जिम्मेदार कारणों में 25 फीसदी हिस्सा, चालकों के यातायात व्यवहार से जुड़ा होता है। इसके बाद सड़क इंजीनियरिंग का नंबर आता है।

एक्ट में भारी जुर्माना

संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में अगर शराब पीकर ड्राइविंग करने का मामला साबित होता है, तो चालक पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगता है। एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पीसीआर का रास्ता रोकने पर भी 10 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। बिना हेलमेट पकड़े जाने पर तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड होता है। ओवर स्पीड और बिना बीमा पॉलिसी के गाड़ी चलाने पर भी दो हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। नाबालिग, गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा गया, तो वाहन मालिक और अभिभावक, दोनों को कसूरवार ठहराया जाएगा। इसमें तीन साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होने का भी प्रावधान है। ट्रैफिक सिग्नल के उल्लंघन पर 500 रुपये जुर्माना होगा। दोबारा यह उल्लंघन होने पर जुर्माना राशि दो हजार रुपये तक पहुंच सकती है। हिट एंड रन केस में पीड़ित परिवारों को दो लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी। बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना, यह जुर्माना भी 100 रुपये से बढ़ा कर 1000 रुपये कर दिया गया है। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन पर बात करना, इस उल्लंघन पर 5000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।

इन कारणों के चलते बढ़ी सड़क हादसों की रफ्तार

- साल 2021 के दौरान हुए सड़क हादसों में 133025 (86.4 फीसदी) पुरुष और 20947 (13.6 फीसदी) महिलाओं की जान गई है।
- दोपहिया वाहन पर बिना हेलमेट वाले 46593 (30.6 फीसदी) चालक सड़क हादसों का शिकार हुए हैं।
- ऐसे 16397 कार सवार, जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, सड़क हादसों में मारे गए।
- ओवरलोड वाहनों की वजह से जो हादसे हुए, उनमें 11011 लोग मारे गए।
- हिट एंड रन के 57415 केस हुए थे, जिनमें 25938 लोगों की मौत हो गई और 45355 लोग घायल हुए।
- कुल सड़क हादसों में से 13.7 फीसदी घटनाएं ऐसी थीं, जिनमें वाहन चालक के पास वैद्य लाइसेंस नहीं था। कुछ चालक ऐसे भी थे, जिनके पास लर्नर लाइसेंस था।
- 2021 में सड़क पर बने गड्ढों के चलते 1481 हादसे हुए हैं।

मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में मोदी को भाजपाइयों ने सुना

कोरबा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सभी राज्यों से आए हुए बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करने एवं उनसे बातचीत करने के कार्यक्रम मेरा बूथ सबसे मजबूत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे जिसका सीधा प्रसारण यूट्यूब पर संपूर्ण देश के लोगों ने देखा। इसी के तहत बाल्को नगर में बाल्को भाजपा मंडल के द्वारा नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में टीवी के माध्यम से पुष्पराज बाल सदन स्कूल में उक्त कार्यक्रम को भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं बूथ संबंधी सदस्यों ने देखा एवं सुना।

कार्यक्रम शुरू होने से पहले बालको के कार्यकर्ताओं को मंडल अध्यक्ष शिवबालक सिंह तोमर ने संबोधित किया एवं संबोधन के लिए नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल को आमंत्रित किया। हितानंद अग्रवाल ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो संबोधन होने वाला है, उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है एवं अपने अपने बूथ पर उसी प्रकार कार्य करने की जरूरत है। जिससे हमारा बूथ सशक्त होगा एवं आगामी चुनाव में सफलता प्राप्त होगी। यदि हम अपने.अपने बूथों पर जीत सुनिश्चित कर लें तो निश्चय ही विधानसभा चुनाव में हमारी जीत होगी एवं सरकार हमारी बनेगी। तत्पश्चात सभी ने प्रधानमंत्री जी के संबोधन मेरा बूथ सबसे मजबूत

को देखा एवं सुना उक्त कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि हितानंद अग्रवाल साथ ही मंडल अध्यक्ष शिवबालक सिंह तोमर, लोकेश्वर चौहान, अर्चना रुणीजा, लखन चंद्रा, शशि चंद्रा, ईश्वर, भगत, घनश्याम पटेल, गंगाराम भारद्वाज, तरुण राठौर, राजू खान, नरेश, गुमान सिंह, डॉ के आर राठौर, आलोक तिवारी हेमलता निर्मलकर मीठी गोस्वामी, रेनू प्रसाद एवं अन्य कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे।

मगरलोड भाजपा मंडल में भी सुना

नगरी। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ-सबसे मजबूत' कार्यक्रम के तहत भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इसी तारतम्य में मगरलोड भाजपा मंडल में प्रोजेक्टर के माध्यम से लाइव प्रसारण को पूर्व विधायक सिहावा श्रवण मरकाम ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सुना।

इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष विजय यदु, सांसद प्रतिनिधि भवानी यादव, कविता यादव, झमिन सिन्हा, बसंत साहू, उर्वशी साहू, वैष्णवशरण साहू, पुरषोत्तम साहू, निर्मल साहू, ज्ञानचंद साहू, मुरली सिन्हा, सुशीला जैन, झानेश्वर साहू, भागा सिन्हा, तुलाराम साहू सहित भाजपा कार्यकर्ता गण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

घटुला में भाजपाइयों ने किया जनसम्पर्क

नगरी। ग्राम घटुला में मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर भारतीय जनता पार्टी बेलरगांव मंडल के द्वारा पर घर-घर जनसंपर्क अभियान व संपर्क से समर्थन एवं सोसाइटी में जन चौपाल लगाकर मोदी सरकार के 9 साल में किए गए कार्यों प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, समर्थन मूल्य उर्वरक सब्सिडी, जैसे प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लोगों को पुस्तिका बांट कर वह मिलकर प्रचार प्रसार किया गया । जिसमें प्रमुख रुप से जिला महामंत्री प्रकाश बैस, जिला मंत्री प्रेमलता नागवंशी, मंडल अध्यक्ष अकबर कश्यप, मंडल महामंत्री राकेश चौबे, जनपद अध्यक्ष दिनेश्वरी नेताम, अजजा मोर्चा जिला अध्यक्ष महेंद्र नेताम, सांसद प्रतिनिधि मोहन पुजारी, नगरी मंडल महामंत्री राजू गोसाई , नगरी महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष सुलोचना साहू, नरसिंह मरकाम, दिव्येन्द्र परिहार, उपसरपंच मोनु साहू, कीर्ति कुमार साहु, हीरा लाल साहू आदि उपस्थित थे।

जंगल में भालू से हुआ सामना, तो जान बचाने भालू से भिड़ा आदिवासी युवक

कोरबा। जिले में पंडो जनजाति के युवक पर जंगली भालू ने हमला कर दिया था। लेकिन जब जान पर बन आयी, तो भागने के बजाए युवक भालू से ही भिड़ गया। दोनों के बीच करीब 10 मिनट तक चले संघर्ष के बाद भालू जंगल की ओर भाग गया। लेकिन इन भिड़ंत में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसका उपचार कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जारी है।

घटना कटघोरा वनमंडल के पसान वन परिक्षेत्र में आने वाले सेमरा सर्किल की है। जहां तिलईडांड वन परिसर में घने जंगल के बीच गांव बनखेता मौजूद है। जिसके आश्रित ग्राम रानीगढ़ी में यह घटना घटी है। गांव में पंडो जनजाति के कई परिवार निवास करते हैं। रानीगढ़ी निवासी बनसराम पंडो(36) एक दिन पहले किसी काम से समीप के गांव गया हुआ था। इसी बीच झमाझम बारिश शुरू हो गयी। बारिश से बचने युवक पहाड़ी के रास्ते घर लौट रहा था। इसी दौरान यहां मौजूद भालू ने बनसराम पर हमला बोल दिया। अपनी जान बचाने के लिए युवक भालू से ही भिड़ गया। जंगली भालू और युवक के बीच यह संघर्ष करीब 10 मिनट तक चलता रहा। जिसके बाद भालू जंगल की ओर भाग गया।

घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी

घटना में बनसराम गंभीर रूप से घायल हो गया है। भालू ने उसके पैर और जांघ पर नाखून से नोंच लिया है। वह खून से लथपथ होकर किसी तरह घर पहुंचा। जिसके बाद इस घटना की जानकारी सरपंच ने कोरबा वन विभाग तक पहुंचाई। उनके लिए भी बारिश के बीच पहाड़ी पर पहुंच पाना संभव नहीं था। चुंकि गांव काफी दुर्गम रास्तों से होकर जंगल के बीच स्थित है। यहां तक एंबुलेंस को पहुंचाना संभव नहीं था। ग्रामीणों ने किसी तरह घायल युवक को मुख्य सड़क तक पहुंचाया। घायल युवक को एंबुलेंस के जरिए कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। युवक बुरी तरह से घायल है।

छत्तीसगढ़ का पहला क्रॉस फ्लाई ओवरब्रिज चालू रायपुर से दुर्ग के बीच का सफर होगा आसान

दुर्ग। भिलाई पावर हाउस चौक पर बना प्रदेश का पहला क्रॉस ओव्हर ब्रिज बुधवार से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। दुर्ग भिलाई से रायपुर आने जाने वालों के लिए यही बड़ी राहत की खबर है। इस ब्रिज की खास बात ये है कि इसे बनाने के लिए पुराने ब्रिज को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया गया और ना ही ब्रिज को तोड़ा या बंद किया गया। पुराने ब्रिज से करीब साढ़े 6 मीटर ऊपर लोहे का आर्क डालकर इस ब्रिज को दोनों ओर से जोड़ा गया। जिसके कारण अब ट्रैफिक सुचारू रूप से चलेगा। इस ब्रिज की लंबाई करीब 16 मीटर है और इसे 66 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है।

इस ब्रिज को निर्माण एजेंसी ने 5 जून तक पूरा करने का वादा किया था। लेकिन एजेंसी ने निर्माण कार्य में देरी की।जिसके कारण इसे 26 जून तक भी पूरा नहीं किया जा सका।लेकिन ब्रिज का एक हिस्सा पूरी तरह से तैयार था। लिहाजा जिला प्रशासन ने निर्माण एजेंसी के साथ ब्रिज का मुआयना किया और आज से इसे खोलने का फैसला किया। वहीं दूसरे तरफ का काम जल्द पूरा कर इसे एक हफ्ते में खोलने का अल्टीमेटम निर्माण एजेंसी को दिया गया है।

आपको बता दें कि दुर्ग से कुम्हारी के बीच कुम्हारी, डबरापारा,पावर हाउस और सुपेला फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण हुआ है। इसमें सबसे पहले कुम्हारी ओवर ब्रिज को रायपुर से दुर्ग की ओर जाने वाली और फिर सुपेला ओवर ब्रिज को शुरु किया जा चुका है। ब्रिज को शुरू करने के बाद अब सुपेला घड़ी चौक पर ना सिर्फ ट्रैफिक का दबाव कम हुआ है। बल्कि दुर्घटनाएं भी कम हो रहीं हैं। सुपेला ब्रिज का

निर्माण 87.20 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। ये ब्रिज चारों ब्रिज की तुलना में सबसे लंबा है।इसकी लंबाई 2100 मीटर है।जो चंद्रा मौर्या चौक से शुरू होकर सुपेला थाना तक जाता है। अब ब्रिज के नीचे मॉडिफिकेशन,सड़क और नाली निर्माण का कार्य चल रहा है।

पावर हाउस का ब्रिज शुरु करने के बाद आखिरी ब्रिज डबरापारा बच जाएगा। जो रेलवे के कारण पूरा नहीं हो सका है। रेलवे लाइन के ऊपर ब्रिज बनने के कारण रेलवे से एनओसी मिलने में देरी हुई।जिसके कारण निर्माण कार्य में देरी हुई,इस ब्रिज के लिए निर्माण एजेंसी ने एप्रोच ब्रिज तैयार कर लिया है। इसके बाद फ्लाईओव्हर का काम खत्म किया जाएगा। 580 मीटर लंबे इस ब्रिज को 55।19 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। ब्रिज की लंबाई 580 मीटर और चौड़ाई 18.50 मीटर है।

आपको बता दें कि सुपेला फ्लाईओव्हर ब्रिज को दिसंबर 2022, कुम्हारी फ्लाईओव्हर को नवंबर 2021, पावर हाउस फ्लाईओव्हर को सितंबर 2022 और डबरापारा फ्लाई ओव्हर को दिसंबर 2022 तक पूरा किया जाना था।लेकिन लेटलतीफी के कारण सभी ब्रिज को पूरा करने में एक से दो साल अधिक का समय लग चुका है।

सिहावा विधायक ने डुमरपाली कोपरा एनीकट मरम्मत कार्य का भूमिपूजन किया

नगरी। सिहावा विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं उपाध्यक्ष मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकारण डॉ लक्ष्मी ध्रुव के मुख्य आतिथ्य में 27 जून को ग्राम डुमरपाली कोपरा एनीकट मरम्मत कार्य भूमिपूजन किया गया। डुमरपाली कोपरा एनीकट मरम्मत कार्य हेतु शासन

द्वारा राशि 102.35 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। डुमरपाली एनीकट के आस-पास पैरी नदी में कोई भी पुल पुलिया निर्मित नही होने के कारण एनीकट से हल्के व भारी वाहनों का अत्यधिक आवागमन होता है जिससे एनीकट की उपरी सतह की कांक्रीट क्षतिग्रस्त हो गया था। जिसे क्षेत्रीय विधायक डॉ लक्ष्मी ध्रुव के अथक प्रयासों से डुमरपाली एनीकट मरम्मत कार्य को बजट में शामिल कर प्रशासकीय स्वीकृति रूपये 102.35 लाख की स्वीकृति दिलाई। इस एनीकट की जल संग्रहण क्षमता 4.0405 मि.घ.मी. और एनीकट की उंचाई 2.50 मी. है।

एनीकट के मरम्मत कार्य पूर्ण होने से ग्राम डुमरपाली, कोपरा, सरकड़ा, नवागांव, धौंराभाठा, नारधा, कपालफोड़ी, अमलीडीह एवं खिसोरा व आसपास के ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा प्राप्त होगी जो क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस अवसर पर लखन लाल ध्रुव पी.सी.सी. सदस्य, सर्वेश बाफ्ना जनपद सदस्य,नारद साहू उपाध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मगरलोड, दउवा लाल पटेल, दया प्रसाद यादव, प्रभुलाल पटेल, मिलाप पटेल वरिष्ठ नागरिक, रामकिशन पटेल, मोहनू पटेल, सूभेराम यादव, सरोज निषाद, लच्छन पटेल, मनोहर निषाद, सिंचाई विभाग सबइंजीनियर एवं अन्य विभागीय अधिकारी व ग्रामीणजन उपस्थित थे।

बरसाती पानी की निकासी निर्वाध गति से हो : महापौर

कोरबा। महापौर राजकिशोर प्रसाद वार्ड क्र. 25 कुआंभट्ठा जनता के बीच पहुंचे। वहाँ के निवासियों ने कुछ स्थानो पर बरसाती पानी के निकासी संबंधी समस्या से महापौर को अवगत कराया। जिसे संज्ञान में लेते हुए महापौर ने निगम के स्वच्छता विभाग के अधिकारियों को इससे तत्काल अवगत कराया एवं मौके पर पहुचंकर स्वच्छता विभाग की टीम द्वारा वार्डवासियों ने जिन स्थानों पर पानी की निकासी बाधित होने की जानकारी दी थी, उन स्थानों पर पहुंचकर साफ-सफाई का कार्य कर बस्ती के पानी की निकासी संबंधी समस्याओं का तत्काल समाधान कराया।

महापौर श्री प्रसाद ने बस्ती वासियों से आग्रह किया कि नालियों में गंदगी, प्लास्टिक आदि न फेकें, उससे नालियो का पानी नहीं निकल पाता है और नालियो के जाम की स्थिति होने की संभावनाएँ बन जाती है। बरसात का पानी निर्वाध गति से बहे, इस हेतु महापौर श्री प्रसाद ने बस्तीवासियों को समझाईश देते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की। महापौर श्री प्रसाद ने बताया कि प्रदेश के राजस्व मंत्री व हमारे क्षेत्र के विधायक श्री जयसिंह अग्रवाल का मानना है कि मूलभूत सुविधाएँ प्रदान कराना

निगम का मुख्य कर्तव्य है। वार्ड को स्वच्छ बनाये रखने में आप सभी का भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आप अपने वार्ड में न तो स्वयं गंदगी करें और न ही किसी को करने देवें, इस प्रकार से अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें।

महापौर श्री प्रसाद ने कहा कि हमारे क्षेत्र के विधायक श्री अग्रवाल द्वारा समय-समय पर प्रत्येक वार्डो के विकास कार्यों के साथ-साथ वार्डों के साफ-सफाई नियमित होती रहे विशेष कर बरसात के पानी का जमाव न होने पावे, नालियो में पानी का जमाव न हो, दवाओं का छिड़काव नियमित रूप से होती रहे, ताकि मच्छरों का प्रकोप कम हो सके, इसके लिए महापौर द्वारा निर्देश दिया गया। श्री प्रसाद ने आगे कहा कि बरसात पूर्व से ही नाले-नालियों की साफ-सफाई का कार्य कराये गये हैं।

प्रमुख समाचार छत्तीसगढ़

तेज बारिश के कारण मिट्टी कटाव से धंसी सड़क

कोरबा। कोरबा जिले में पिछले कुछ दिनों से रुक-रुककर हो रही झमाझम बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। सुबह से लेकर रात तक बारिश होने के कारण लोगों का जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। स्कूल दफ्तर या फिर दैनिक रोजगार करने वाले लोग लगातार हो रही बारिश से काफी प्रभावित हुए हैं। तेज बारिश के कारण जिले के ग्रामीण अंचल की एक सड़क बह गई है। सड़क का एक हिस्सा बह जाने के कारण लगभग डेढ़ दर्जन गांवों का संपर्क टूटा गया है। पाली विकासखंड के पोड़ी-पाली मार्ग में गुंजन नाला पर निर्मित अस्थाई सड़क का बड़ा हिस्सा पानी के तेज बहाव में बह गया। जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

मरवाही के जंगलों में गजराज का आतंक, कई घरों को उजाड़ा

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। मरवाही के जंगल में इस समय हाथियों के एक दल ने डेरा जमा लिया है। आलम यह है कि हाथियों का झुंड अब गांव के अंदर घुस कर लोगों के घरों को तहस-नहस कर रहा है। इसके चलते ग्रामीण रतजगा करने को मजबुर हो गए हैं। सूत्रों ने बताया कि हाथियों का मूव्हमेंट इस समय सबसे ज्यादा मरवाही वन मंडल में दर्ज किया जा रहा है। यहां हाथियों के एक दल ने गांव में प्रवेश कर करीब आधा दर्जन ग्रामीणों के घरों को उजाड़ दिया है। इसके चलते ग्रामीणों में दहशत व्याप्त हो गया है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद अब वन विभाग के कर्मचारी हाथियों पर नजर रखे हुए हैं और हर संभव प्रयास करते हुए इन्हें आबादी से दूर रखने का जतन कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणजन भी अपने घरों और फसलों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं। बताया जाता है कि हाथियों को दूर रखने के लिए ग्रामीण ग्रुप बनाकर बारी-बारी से पहरेदारी कर रहे हैं। बताया जाता है कि हाथियों का यह दल काफी समय से इस इलाके में सक्रिय बना हुआ है।

सड़क पर बैठे 16 मवेशियों को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा

बिलासपुर। हाईवे की चपेट में आने के कारण 16 मवेशियों की मौके पर मौत हो गई। यह हादसा देर रात इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ। दर्जनों से ज्यादा मवेशियों को टक्कर मारकर चालक हाइवा छोड़कर फरार हो गया। यह मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सड़क हादसे का शिकार हुई असहाय इन मवेशियों के कारण यह एरिया कुछ समय तक अवरुद्ध रहा। इस घटना की सूचना पुलिस-प्रशासन को दी गई। पुलिस-प्रशासन जैसे-तैसे इन मृत मवेशियों को बीच सड़क से एक तरफ करवाकर इंडस्ट्रियल एरिया को व्यवस्थित चालू कराया। मवेशियों की धमाचौकड़ी से चलने वाले वाहन चालक परेशान हैं। बिलासपुर इंडस्ट्रियल एरिया पर मवेशियों का जमावड़ा देखने को मिलता है। घूम रहे पशुओं से आए दिन दुर्घटनाएं होने से लोग परेशान हो रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि यह मवेशी आए दिन आपस में भिड़ जाते हैं, जिससे सड़क से निकलने वाले वाहन चालक भी घायल हो जाते हैं।

तेज वर्षा से ढहा गुंजन नाला का रपटा, आवागमन बाधित

कोरबा। मंगलवार को सुबह से जारी वर्षा से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। पाली विकासखंड के ग्राम पुलाली के पास गुंजन नाला में निर्मित रपटा के टूटने से पाली और रतनपुर के बीच आसपास के 17 गांवों के लोगों का आवागमन ठप हो गया है। मार्ग में छह करोड़ की लागत से नवीन पुल का निर्माण स्वीकृत है। दो साल बाद भी काम पूरा नहीं हुआ है। लोगों को हर साल इस मार्ग में आवागमन की समस्या से जूझना पड़ता है। वहीं दर्री बांध में उपरी क्षेत्र से पानी का भराव होने से 10 नंबर गेट को एक फीट खोल दिया गया है। मानसून की सक्रियता और झमाझम वर्षा का अब चौतरफा असर दिखने लगा है। नदियों में अब भी पानी का बहाव कम है, वहीं छोटे नाले उफान पर आने लगे हैं। पाली से रतनपुर के लिए निर्मित बायपास मार्ग में ग्राम पुलाली के पास गुंजन नाला का रपटा दोपहर तीन बजे टूट गया। बताना होगा कि नाला में नवीन पुल का निर्माण कार्य अभी जारी है। वैकल्पिक आवागमन के लिए रपटा का निर्माण किया गया था।

केनरा बैंक देगी 10 हजार की क्षतिपूर्ति और भरेगी जुर्माना

जगदलपुर। जिला उपभोक्ता आयोग ने एक प्रकरण में एटीएम से राशि प्राप्त नही होने पर केनरा बैंक को 10 हजार रूपये की क्षतिपूर्ति और उस पर वाद प्रस्तुति दिनांक से 7 प्रतिशत ब्याज देने, सहित मानसिक क्षति हेतु 5 हजार रूपये एवं वाद व्यय 3 हजार रूपये दिए जाने का आदेश पारित किया गया है। जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष सुजाता जसवाल सदस्य आलोक दुबे और सीमा गोलछा की संयुक्त पीठ ने पाया कि केनरा बैंक द्वारा निर्धारित समय पर राशि अदा नही कर तथा वांछित जानकारी प्रदान नही कर सेवा में कमी और व्यावसायिक कदाचरण किया है। बैंक के द्वारा अपने समर्थन में कोई प्रमाणिक दस्तावेज सीसीटीवी फुटेज, एटीएम स्टेटमेंट पेश नहीं किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जगदलपुर निवासी परिवादी मनजीत बसरा का केनरा बैंक में खाता है, उसने केनरा बैंक के अपने खाते के एटीएम का उपयोग नयापारा स्थित भारतीय स्टेट बैंक की एटीएम में किया था। उसके केनरा बैंक खाते से10 हजार रूपये काट लिए गए थे, पर राशि उसे एटीएम से प्राप्त नहीं हुई थी।

मानसून ने किसानों के लिए अनुकूल बोआई की राह खोली

कोरबा। मानसून की सक्रियता ने जिले के किसानों की व्यस्तता बढ़ा दी है। एक जून से अब जिले में 984.4 मिलीमीटर वर्षा हुई है। पिछले चार दिनों के भीतर हुई 358.9 मिलीमीटर वर्षा ने धान की बोआई में तेजी ला दी है। जिले में 17 प्रतिशत बोआई पूरी हो चुकी है। जिन किसानों ने सूखा बोआई की थी उनके खेतों में अब धान की हरियाली दिखने लगी है। वर्षा का साथ रहा तो आगामी 15 दिन के भीतर खेतों में थरहा रोपाई का काम शुरू हो जाएगा।

मानसून ने किसानों के लिए अनुकूल बोआई की राह खोल दी है। खरीफ वर्ष में इस बार जिला कृषि विभाग ने 97,040 हेक्टेयर में अनाज की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें 83,130 हेक्टयर में धान और 13ए910 हेक्टेयर में कोदो, कुटकी, रागी और मक्का की बोआई को वरीयता दी गई है। धान के अलावा किसानों

ने दलहन और तिलहन के बोआई की भी तैयारी शुरू कर दी है। धान के बदले अन्य फसल को बढ़ावा देने के लिए इस बार दलहन के रकबा को जहां 10 हजार 920 से बढ़ाकर 16 हजार 200 कर दिया गया है। वहीं तिलहन तिलहन के रकबा को 3,510 से बढ़ाकर 5,200 हेक्टेयर कर दिया गया है।

दलहन और तिलहन की बोआई धान बोआई के बाद होगी। बहरहाल कृषि विभाग की ओर इस बार धान खेती के लिए किसानों को रोपा व बोता विधि को अपनाने के लिए कहा जा रहा है। दोनों की विधि से खेती के लिए 9,157 हेक्टेयर में खेती की जा चुकी है। जिन किसानों ने सूखा बोआई किया था। उनके खेतों धान की हरियाली अब दिखने लगी है। जिले में ज्यादातर किसान रोपा विधि से खेती करते हैं। खास बात यह है कि थम.थम कर हो रही वर्षा से खेतों में पानी भराव की नौबत नहीं। ऐसे में किसानों के खेतों की जोताई कराने में आसानी हो रही है। आसमान में बदली के साथ वर्षा जारी है। वहीं उमस का असर भी बरकरार है। किसानों की माने तो लगातार वर्षा फसल के तैयार होने में बाधा होगी। वर्षा के अलावा धूप भी फसल को तैयार होने के लिए जरूरी हैं। बताना होगा कि बीते वर्ष की तुलना में इस बार मानसून की सक्रियता तेजी से बढ़ी है। गांव की गलियों के बजाए अब खेतों में लोगों की हलचल बढ़ गई है।

खाद और बीज के बढ़े दाम से खेती महंगी हो गई हैं। बीते वर्ष की तुलना में अनाज के बीज जैसे धानए कोदोए रागी कीमत में 10 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वहीं दलहन और तिलहन के दाम में आठ प्रतिशत की बढ़त हुई। जिला प्रशासन की ओर से गोबर खाद को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। जिले के 412 में 348 ग्राम पंचायतों गोठान की शुरूआत की गई है। खाद तैयार करने गोठानों की संख्या 100 से भी कम होने की वजह किसानों को गोबर खाद से वंचित होना पड़ रहा। दूसरी ओर पेट्रोलिय के दाम बढ़ने से ट्रैक्टर से जुताई 1500 रूपये प्रति घंटा लिया जा रहा है। बीते वर्ष की तुलना में यह भी 10 प्रतिशत अधिक है। भले ही खेतों को बोआई के लिए वर्षा साथ मिल रहा हैए लेकिन एक जून से अब तक हुई वर्षा जलाशयों के लिए पर्याप्त नहीं है।

नक्सलियों ने पर्चे फेंककर कर्मचारी अधिकारियों पर नामजद आरोप लगाया

बीजापुर। नक्सलियों के मद्देड़ एरिया कमेटी ने बीजापुर जिले के भोपालपटनम और रुद्रराम के बीच पर्चे फेंककर ठेकेदार, कर्मचारी और अधिकारियों पर नामजद आर्थिक लेन-देन में कमीशन का आरोप के साथ कोरंडम, रेत खदान, सागौन सहित कई प्रकार के सम्पदा के तस्करी का आरोप लगाया है।

नक्सली पर्चे में भोपालपटनम नगर पंचायत के अन्तर्गत आने वाला पुल-पुलिया, सड़क, सीसी रोड, केनाल, प्रति टेंकर 800-1000 रुपये, मकान, गाड़ी से तहसीलदार सूर्यकांत, एसडीओपी भावेश समरथ, थाना प्रभारी नरेश साहू, सब-इंजीनियर सुधीर वासम और सचिव सभी लोग एकत्रित होकर हर काम में लाखों रूपये की वसूली कर खा रहे हैं। सचिव कोरम विजय, फारेस्ट गार्ड जोगेंद्र यादव, डिप्टी अजय कोरम, थाना प्रभारी नरेश साहू, गौतम राव रेत खदान ठेकेदार इनके नेतृत्व में सागौन लट्ठा, फाराओ को चोरी-चुपक। तेलंगाना-महाराष्ट्र में बेचकर लाखों रूपये कमा रहे है। नक्सली पर्चे में कहा गया है कि लोकसभा-विधानसभा से ऊपर ग्राम सभा अधिकार का उलंघन करके सूर्यकांत तहसीलदार, पटवारी के नेतृत्व में मद्देड़-पटनम में रहने वाले साधारण गरीब आदिवासियों के घरों को जेसीबी, डोजर से गिरा रहे हैं ओर उस जमीन को कब्जा करके दूसरो को बेचा जा रहा है। मद्देड़ एरिया कमेटी का कहना है कि जंगल काट के लट्ठा-फारा बेचने वालों को मौत का सबक सीखा कर जल-जंगल- जमीन को बचाएं रखेंगे। घरों को तोड़- फोड़ जमीन कब्जा धारियों को मार के भगाओ। पैसा लूटने वाले तहसीलदार एवं पटवारियों को भगाओ। साधारण आदिवासियों को जीने नही देने वाले आरएसएस भाजपा संगठन का विरोध करेंगे। विदेशी मदिरा दुकान में दाम बढ़ा कर बेचने वाले के ऊपर कार्यवाही किया जायेगा। लोकल गांव में विदेशी दारू बेचना बंद किया जाये, जो बंद नहीं करेगा उसके ऊपर कार्यवाही किया जाएगा।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

यूसीसी को लोगों पर थोपा नहीं जा सकता : चिदंबरम

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की पुरजोर वकालत किए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि एजेंडा आधारित बहुसंख्यक सरकार इसे लोगों पर थोप नहीं सकती क्योंकि इससे लोगों के बीच विभाजन बढ़ेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी, महंगाई और घृणा अपराध जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए समान नागरिक संहिता की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समान नागरिक संहिता का इस्तेमाल समाज के ध्रुवीकरण के लिए कर रही है। चिदंबरम ने एक ट्वीट में कहा, प्रधानमंत्री ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूसीसी साधारण प्रक्रिया है। उन्हें पिछले विधि आयोग की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए जिसमें कहा गया है कि यह इस वक्त सुसंगत नहीं है। पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने कहा, भाजपा की कथनी और करनी के कारण देश आज बंटा हुआ है। ऐसे में लोगों पर थोपा गया यूसीसी विभाजन को और बढ़ाएगा।

कैग की एंट्री के बाद आप पर हमलावर हुई भाजपा व कांग्रेस

नईदिल्ली। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भाजपा कैग के फैसले का स्वागत करती है, कैग ने आज केजरीवाल के भ्रष्टाचार के प्रतीक शीशमहल की जाँच करने का फैसला लिया है जिससे अब केजरीवाल का सच जनता के सामने आ जाएगा। भाजपा के रामवीर सिंह विधूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली के टैक्सपेयर्स के 179 करोड़ रुपए लुटाकर राजमहल बनाने की जाँच केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिश पर कैग द्वारा करने का हम करते हैं स्वागत। अब हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। कांग्रेस ने कहा कि पुनर्निर्माण पर ''171 करोड़ रुपये के भारी खर्च'' के मामले में विस्तृत आपराधिक जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने ऑडिट कराए जाने की सिफारिश का स्वागत करते हुए कहा कि यह बहुत दुखद है कि जनता के पैसे का इस तरह से 'शीशमहल' बनाने में दुरुपयोग किया गया।

अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन डील पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

नईदिल्ली। कांग्रेस ने अमेरिका से 31 ड्रोन खरीदे जाने को लेकर सरकार के कदम पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने 31 ड्रोन की कीमतों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने साफ तौर पर कहा कि राफेल सौदे में जो हुआ, वही प्रीडेटर ड्रोन सौदे में दोहराया जा रहा है। कांग्रेस इसे अधिक कीमतों पर खरीदने का आरोप लगा रही है। एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के पवन खेड़ा ने कहा कि पीए मोदी के महंगे शौक देश को महंगे पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो प्रीडेटर ड्रोन दूसरे देश 4 गुना कम कीमत पर खरीदते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी 880 करोड़ रुपए प्रति ड्रोन के हिसाब से खरीद रहे हैं। यानि हम 25 हजार करोड़ रुपए के 31 ड्रोन खरीद रहे हैं। खेड़ा ने कहा कि राफेल सौदे में जो हुआ, वही अमेरिका के साथ प्रीडेटर ड्रोन सौदे में दोहराया जा रहा है। दूसरे देश उन्हीं ड्रोनों को चार गुना से भी कम कीमत पर खरीद रहे हैं।

ईडी ने नौकरी घोटाला मामले में टीएमसी नेता को समन किया

कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने स्कूल भर्ती घोटाले में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी जांच के सिलसिले में बुधवार को तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद (टीएमसीपी) की प्रदेश अध्यक्ष सायोनी घोष को समन जारी किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घोष को 30 जून को पूर्वाह्न 11 बजे कोलकाता स्थित ईडी के कार्यालय में अधिकारियों के समक्ष पेश होने को कहा गया है। उन्होंने कहा, ''मामले में गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के दौरान घोष का नाम कई बार सामने आया। हमारे पास इस घोटाले में गिरफ्तार एक आरोपी के साथ कई सौदों में घोष की संलिप्तता के बारे में साक्ष्य मिले हैं। हमने उन्हें (घोष को) शुक्रवार को कुछ खास दस्तावेज लाने को कहा है।'' इस महीने की शुरुआत में ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को इस घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया था।

राहुल के खिलाफ ट्वीट करना अमित मालवीय को पड़ा भारी

बेंगलुरु। कर्नाटक कांग्रेस ने कथित तौर पर राहुल गांधी का मजाक उड़ाने के लिए बुधवार को बेंगलुरु में बीजेपी नेता और आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मालवीय पर राहुल गांधी के एक एनिमेटेड वीडियो को लेकर मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस के रमेश बाबू की शिकायत के बाद, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उनके ट्वीट के लिए बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पीएस में आईपीसी की धारा 153 ए 120 बी 505 (2), 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस बीच, ताजा घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की और कहा कि नेताओं को देश के कानून का पालन करने में समस्या है। इसके अलावा, उन्होंने भगवा पार्टी से उस एफआईआर को इंगित करने के लिए कहा जिसे भाजपा समझती है कि यह गलत इरादे से दर्ज की गई है।

पसमांदा मुसलमान बनेंगे तुरुप का एक्का

2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए उपयोगी साबित होंगे

नईदिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 की चर्चा के बीच अचानक पसमांदा मुसलमान सुर्खियों में आ गये हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल से चुनावी अभियान का आगाज करते हुए पसमांदा मुसलमानों की बदहाल स्थिति पर चर्चा की और इस समाज को राजनीति का शिकार भी बताया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में जो भी बोलते हैं, उसकी चर्चा निश्चित रूप से होती है। जिस तरह से उन्होंने चुनावी शंखनाद करते हुए पसमांदा मुसलमानों की बदहाल स्थिति के बारे में चर्चा की है, उससे राजनीतिक गलियारों में नये बहस को जन्म दे दिया है। पीएम के भाषण से तो एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी के फोकस में पसमांदा मुसलमान होंगे। उनके मुद्दे को लेकर बीजेपी चुनावी मैदान पर उतरेगी। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पसमांदा मुसलमानों के बीच जाने की सलाह दी। साथ ही पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता को लेकर जो भ्रम की स्थिति उनके बीच बनी है, उसे दूर करने की भी सलाह दी है। पीएम मोदी की सलाह को विपक्षी एकता के खिलाफ दांव माना जा रहा है।

पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा, वोट बैंक की राजनीति के कारण पसमांदा (सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमान) मुसलमानों के साथ बराबरी का व्यवहार भी नहीं किया जाता है जबकि सरकार ने बिना किसी भेदभाव के वंचितों (पसमांदा मुस्लिमों सहित) के लिए काम किया है। मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, दक्षिण भारत, खासकर केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु और कई अन्य राज्यों में तुष्टीकरण की नीति के कारण कई जातियां विकास से पीछे रह गईं। पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष हम पर आरोप लगाते हैं लेकिन हकीकत यह है कि वे मुसलमान, मुसलमान करते हैं। अगर वे वास्तव में मुसलमानों के हित में (काम) कर रहे होते, तो मुस्लिम परिवार शिक्षा और नौकरियों में पीछे नहीं होते। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय मुसलमानों को यह समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़काकर उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पसमांदा मुसलमानों की चर्चा की कि उससे साफ है कि बीजेपी की नजर इस समाज पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुल मुस्लिम

वोटों में पसमांदा मुसलमानों की भागीदारी सबसे अधिक मानी जाती है। मुस्लिम अगर एकजुट होकर अगर किसी के पक्ष में वोट कर दें, तो उसकी जीत मानी जाती है। इसका उदाहरण कर्नाटक चुनाव में भी देखने को मिली। यूपी, बिहार, झारखंड, असम और पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटरों की संख्या अच्छी तादाद में है। वैसे में बीजेपी हिंदू वोट के साथ मुस्लिम वोट पर अपनी नजर बनाये हुए है।

भाजपा की चुनावी तैयारी, धर्मेंद्र भूपेंद्र को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी

2024 चुनाव को लेकर भाजपा अभी सही अपनी तैयारियों में जुट गई है। हाल के दिनों में हमने देखा कि कैसे संगठन में बड़े फेरबदल को लेकर भाजपा की बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहे। इस बैठक के बाद तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। फिलहाल मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में पार्टी की ओर से देश के अलग-अलग हिस्सों में सरकार के कामकाज को जबरदस्त तरीके से बताया जा रहा है।

2024 चुनाव को लेकर भाजपा अभी सही अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद भाजपा ने कई बड़े बदलाव करने को लेकर योजनाएं बनाई हैं। जानकारी के मुताबिक के जल्द ही संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती हैं। यह दोनों नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी के काफी विश्वसनीय हैं। संगठन में काम करने का इन्हें लंबा अनुभव है और नतीजे भी सामने आए हैं। साथ ही साथ कुछ राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष पर बदल जा सकते हैं जिसमें गुजरात और कर्नाटक शामिल है। दावा किया जा रहा है कि 30 जून के बाद कभी भी भाजपा की ओर से इन बदलाव का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि, अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहर इस पर नहीं लगी है।

2024 चुनाव की तैयारियों के लिहाज से मोदी मंत्रिमंडल में कई बड़े फेरबदल किए जा सकते हैं। हालांकि, इसको लेकर अब तक कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। लेकिन अगर इस फेरबदल की नौबत आती है तो मानसून सत्र से पहले ही यह हो सकता है। जानकारी के मुताबिक 17 जुलाई से संसद के मानसून सत्र शुरू होगा। ऐसे में कैबिनेट में फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। पार्टी 2024 चुनाव के लिहाज से रणनीति बनाने में जुटी हुई है।

मोदी सरकार का किसानों को तोहफा, गन्ने पर एमएसपी में बढ़ोतरी का हुआ ऐलान

केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आज मोदी कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में गन्ना किसानों के लिए एमएसपी में बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने चीनी सीजन 2023-24 के लिए गन्ना किसानों के लिए 315 रुपये प्रति क्विंटल के अब तक के उच्चतम उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस निर्णय से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों के साथ-साथ चीनी मिलों और संबंधित सहायक गतिविधियों में कार्यरत 5 लाख श्रमिकों को लाभ होगा। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को संसद में लाया जाएगा और साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 को रद्द किया जाएगा।

विपक्षी एकता को झटका, आप ने समान नागरिक संहिता को दिया समर्थन

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी ने समान नागरिक संहिता को अपना समर्थन दे दिया है। पार्टी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता देश के लिए बेहद आवश्यक है और इसे लाने से सभी समुदायों को एक समान मंच पर लाने में सफलता मिलेगी। उसका यह कदम विपक्षी दलों की एकता के लिए तगड़ी चोट साबित हो सकता है।

अरविंद केजरीवाल विपक्ष की अपनी पारंपरिक राजनीति से अलग स्टैंड लेने के लिए जाने जाते रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने राम मंदिर और संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के मुद्दे का समर्थन किया था। इसके लिए उन्हें विपक्ष के दूसरे दलों का कड़ा विरोध भी झेलना पड़ा था। लेकिन अपनी राजनीति की अलग पिच तय करते हुए अरविंद केजरीवाल ने इन मुद्दों का समर्थन किया था।

उमर अब्दुल्ला ने विपक्षी दलों की एकता बैठक के दौरान भी अरविंद केजरीवाल पर इसी बात पर हमला बोला था कि उन्होंने धारा 370 की समाप्ति पर इसे देशहित में लिया गया फैसला बताया था, लेकिन आज जब उनके खिलाफ दिल्ली अध्यादेश का मामला आ गया है तब वे सभी विपक्षी दलों से इसके खिलाफ समर्थन मांग रहे हैं। कथित तौर पर इसी कारण अरविंद केजरीवाल को विपक्षी दलों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया था।

बड़ा प्रश्न है कि अरविंद केजरीवाल यह राजनीति क्यों अपनाते हैं। दरअसल, भाजपा एक रणनीति के तहत कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही है, लेकिन भाजपा की यही कोशिश आम आदमी पार्टी के संदर्भ में सफल नहीं हो पाई। भाजपा अरविंद केजरीवाल पर भी मुस्लिम तुष्टीकरण करने का आरोप लगाती रही है। इसी के तहत दिल्ली सरकार द्वारा सभी मौलवियों को हर महीने 25 हजार रुपये का वेतन देने और हिंदू-सिख धर्म के पुजारियों को कोई वेतनमान न देने का मामला भी वह जोरशोर से उठाती रही है। लेकिन इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप खास असर नहीं डाल सका है।

संभवतया इसका यह कारण रहा है कि अरविंद केजरीवाल दिवाली पर भगवान गणेश-लक्ष्मी की

पूजा करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो छठ में यमुना पर पूजा करने भी पहुंच जाते हैं। हनुमान शोभा यात्राओं पर विरोध का आरोप लगने पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता गली-गली हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हैं। जब मनीष सिसोदिया को जेल भी जाना पड़ता है तो वे अपने साथ गीता की पुस्तक लेकर जाते हैं।

आम आदमी पार्टी ने अपना चरित्र ऐसा बनाया हुआ है कि वह राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्र का साथ देती हुई नजर आती है, तो हिंदुत्व के मुद्दे पर लोगों को अयोध्या के दर्शन भी करवाती है। यही कारण है कि भाजपा उन पर हिंदू विरोधी होने का आरोप अब तक कारगर तरीके से साबित नहीं कर पाई है। चूंकि वे राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा और कांग्रेस दोनों का विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए वे एक साथ हिंदुत्व के पुरोधा, राष्ट्रीय गौरव की राजनीति के नायक और मुस्लिमों के हितैषी बनना चाहते हैं। चुनाव परिणाम और आम आदमी पार्टी का हर राज्यों में हो रहा विस्तार यह बताने के लिए पर्याप्त है कि उनका यह राजनीतिक दांव अब तक कारगर साबित हुआ है। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि वे समान नागरिक संहिता के समर्थन में हैं। लेकिन इसे लाने के पहले देश के हर वर्ग और हर समुदाय से व्यापक बातचीत की जानी चाहिए और सबके हितों-परंपराओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे देश में अलग-अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं और अनेक आदिवासी समुदायों की परंपरा हमसे बहुत अलग है। ऐसे में कोई कानून लाने से पहले सभी से विचार विमर्श करना आवश्यक है।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत आने को लेकर पीसीबी के बयान पर आईसीसी का जवाब

दुबई। वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल तय होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की आनाकानी शुरू हो गई है। उसने मंगलवार को एक बयान में कहा था कि पाकिस्तान सरकार की ओर से उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) नहीं मिली है। इसलिए वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने को लेकर उनकी स्थिति अभी साफ नहीं है। इस पर आईसीसी ने जवाब दिया है। आईसीसी ने कहा है कि पीसीबी ने एग्रीमेंट साइन किया है और उम्मीद है कि वह इस पर काबिज रहेंगे।

आईसीसी ने एक बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने पाकिस्तान की स्थिति को लेकर कहा, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस एग्रीमेंट से पलटेंगे नहीं और भारत आएंगे। वर्ल्ड कप में भाग ले रही सभी टीमें अपने देश के नियम और कानूनों से बंधी हैं और हम इसका सम्मान भी करते हैं। हालांकि, हमें पूरा भरोसा है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने भारत जरूर आएगा। आईसीसी के मौजूदा अध्यक्ष जॉर्ज बार्कले हैं। आईसीसी और बीसीसीआई ने अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान के मैच के वेन्यू को बदलने की पीसीबी की मांग को ठुकरा दिया था। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बात सामने आई है कि पाकिस्तान भारत से अहमदाबाद में मैच नहीं खेलना चाहता था। ड्राफ्ट शेड्यूल जारी होने के बाद पीसीबी ने आईसीसी और बीसीसीआई से अफगानिस्तान के खिलाफ मैच बेंगलुरु में और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच चेन्नई में शिफ्ट करानी की मांग की थी। हालांकि, शेड्यूल आने के बाद यह तय हो गया है कि पाकिस्तान-अफगानिस्तान मैच चेन्नई में ही और पाकिस्तान-ऑस्ट्रेलिया मैच बेंगलुरु में खेला जाएगा। साथ ही पाकिस्तान को भारत के खिलाफ 15 अक्तूबर को अहमदाबाद में ही मैच खेलना होगा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

शेयर बाजार में रौनक, सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर

मुंबई। वैश्विक बाजारों से मिले मिश्रित संकेतों के बीच आज सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को घरेलू शेयर बाजार में लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में तेजी का सिलसिला जारी रहा। बाजार जबरदस्त उछाल के साथ हरे निशान पर बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स लगभग 500 अंकों की उछाल के साथ नए ऑलटाइम हाई पर बंद हुआ। निफ्टी भी 155 अंक चढ़कर 18,972.10 अंक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 499.39 अंक यानी 0.79 फीसदी की बढ़त के साथ 63,915.42 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 64,050.44 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 63,554.82 तक आया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 154.70 अंक यानी 0.82 फीसदी चढ़ा। निफ्टी दिन के अंत में 18,972.10 अंक पर बंद हुआ।

हैपिएस्ट माइंड्स एआई में करेगी दोगुना निवेश

नईदिल्ली। अशोक सूता के नेतृत्व वाली हैपिएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजिज अगले 24 महीने में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) में अपना निवेश दोगुना करने की योजना बना रही है। कंपनी के शीर्ष अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अलबत्ता उन्होंने यह नहीं बताया कि वे कितना निवेश करेंगे। कंपनी की एनालिटिक्स और एआई पेशकश में एआई, मशीन लर्निंग और सांख्यिकीय प्रारूप का उपयोग करते हुए आधुनिक एनालिटिक्स का कार्यान्वयन तथा भारी मात्रा में डेटा को संभालने के लिए बड़े डेटा प्लेटफार्मों की इंजीनियरिंग शामिल है। वित्त वर्ष 23 के दौरान एनालिटिक्स और एआई से राजस्व 12.2 प्रतिशत रहा है। इस समय बाजार जिस तरह आगे बढ़ रहा है, यह उसके लिए तर्कसंगत प्रतिक्रिया है। एआई में लगातार अधिकाधिक निवेश होगा क्योंकि मुख्य रूप से डिजिटल का झुकाव या धार इसी में बढ़ रही है।

फार्मा कंपनी ल्यूपिन अलग करेगी अपना एपीआई कारोबार

नईदिल्ली। फार्मा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ल्यूपिन आंतरिक पुनर्गठन कवायद के तहत अपना सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई) कारोबार अलग कर सकती है। खबरों में यह दावा किया गया है। एपीआई ऐसी थोक दवा या सामग्री होती है, जिसका उपयोग दवा बनाने में किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फार्मा कंपनी ज्यादा फायदा कमाने के लिए अपना एपीआई कारोबार अलग करने पर विचार कर रही है। इस विभाजन के बाद एपीआई कारोबार को संभावित रूप से सूचीबद्ध किया जा सकता है या उसकी हिस्सेदारी बिक्री की जा सकती है। ल्यूपिन के प्रवक्ता ने बताया कि कंपनी में हम अपने हितधारकों के लिए मूल्य सृजन के लिए रणनीतिक विकल्पों का लगातार मूल्यांकन करते हैं। हम विकास और विस्तार के अवसर तलाशते हुए अपने मुख्य कारोबारी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी रणनीति के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

एसबीआई पेंशन में खरीदेगी एसबीआई कैपिटल की 20 फीसदी हिस्सेदारी

नईदिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई पेंशन फंड में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स की पूरी 20 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगी। इस बात की जानकारी बैंक ने दी। एसबीआई ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि हिस्सेदारी के ट्रांसफर के लिए सभी नियामक की मंजूरी अभी लेना बाकी है। एसबीआई द्वारा एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई जानकारी के अनुसार, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ सेंट्रल बोर्ड (ईसीसीबी) की कार्यकारी समिति ने एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की पूरी 20 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि एसबीआई पेंशन फंड देश के 10 सबसे बड़े फंड मैनेजर्स में से सबसे अधिक फंड मैनेज करती है।

गेमचेंजर साबित हो सकता है लघु उद्योगों का अपना स्टॉक एक्सचेंज

पंकज गांधी

प्रतिवर्ष 27 जून को विश्व एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। लघु उद्योगों के सामने आनेवाली समस्याओं पर कम से कम इस दिन विचार किया जाता है लेकिन इस पर विमर्श के दौरान इस वर्ग की मूलभूत समस्या पूंजी और बड़ी मछली के बीच छोटी मछली के रूप में दब जाना गायब रहता है। इसका समाधान तभी होगा जब रेगुलर स्टॉक एक्सचेंज से इतर एमएसएमई के लिए समर्पित स्वतंत्र स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना होगी। जब तक यह सुधार नहीं होगा इस वर्ग का स्वतंत्र विकास हमेशा संघर्ष करेगा।

हम सबको मालूम है एमएसएमई सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। एमएसएमई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल एमएसएमई 6.33 करोड़ हैं, और उसमें से 6.08 करोड़ यानि लगभग 95.98 फीसदी एमएसएमई एकल व्यवसाय में हैं। यह दर्शाता है कि एमएसएमई द्वारा कॉरपोरेट फॉर्म या अन्य संगठित रूप बहुत कम पसंद किये जा रहें हैं और यही कारण है कि इस सेक्टर की एक बहुत बड़ी संख्या अनमैप्ड और अपंजीकृत हैं।

भारत में यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है क्योंकि यह अन्त्योदय के सिद्धांतों के अनुसार अंतिम छोर के भारतीय के विकास में योगदान देता है। वर्ष 2018-19 के रिपोर्ट के अनुसार एमएसएमई अपनी विशाल वितरित उपस्थिति के साथ करीब करीब 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार, जीडीपी में 29 फीसदी तो जीवीए में 31.83 फीसदी और निर्यात में 48.10 फीसदी का योगदान दे रहा है।

इतना सब होने के बावजूद भी इस सेक्टर की सबसे बड़ी चिंता इसका बड़ी संख्या में अनमैप्ड और अपंजीकृत होना है।

इसमें बड़ी संख्या में लोग एकल व्यवसाय में हैं और लगातार नकदी संकट से जूझते रहते हैं चाहे वह कार्यशील पूँजी हो या स्थाई पूंजी। जबकि इनके मुकाबले बड़े उद्यम के लिए कार्यशील पूंजी एवं स्थाई पूंजी की उपलब्धता अधिक है। एक बड़े संस्थागत प्रयास के रूप में इनके लिए पूँजी बाजार को आकर्षक बनाना जरुरी है जिस कारण ये व्यवसाय के अनौपचारिक फॉर्म छोड़कर औपचारिक फॉर्म में आएं। उनकी समस्या को एमएसएमई के लिए समर्पित स्टॉक एक्सचेंज बनाकर दूर किया जा सकता है। आज की तारीख में देश के दो बड़ी स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपनी व्यवस्थाओं के अधीन एमएसएमई के लिए अलग से प्रकोष्ठ खोले हुए हैं लेकिन यह बड़े बरगद के नीचे छोटे पेड़ों के न फूलने फलने लायक परिस्थिति बनती है। पूर्व एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गड़करी भी कुछ माह पहले राष्ट्रीय एमएसएमई स्टॉक एक्सचेंज बनाने की बात कर रहे थे लेकिन वह एक स्वतंत्र स्टॉक एक्सचेंज की बजाय इन बड़े बरगद रूपी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अधीन ही बात कर रहे थे।

एमएसएमई को अगर लम्बी अवधि के हिसाब से पूंजीगत मजबूती देनी है और बड़ी कंपनियों के बराबर मैदान देना है तो उन्हें स्टॉक एक्सचेंज की मजबूती देनी पड़ेगी। लेकिन यह तब तक संभव नहीं है जब तक एमएसएमई का एक स्वतंत्र स्टॉक एक्सचेंज ना बने। पूरे देश के करीब 15% एमएसएमई यूपी से आते हैं और बिहार को जोड़ दें तो करीब एक चौथाई इन्हीं दोनों राज्यों से हैं। इसलिए अगर ऐसा स्टॉक एक्सचेन्ज कानपुर में बना दिया जाए तो दोनों राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। मुंबई बड़े उद्यम का प्रतिनिधि और यूपी एमएसएमई का प्रतिनिधि पूंजीबाजार में करे तो भारत का आर्थिक संतुलन बनाया जा सकता है।

हालांकि आज भी छोटी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंजों में खुद को सूचीबद्ध कर सकती हैं, लेकिन आमतौर पर वे बीएसई और एनएसई की पात्रता मानदंडों को पूरा करने में अपने आप को अक्षम पाती हैं। दुनिया भर में भी लगभग सभी प्रमुख पूंजी बाजारों ने एमएसएमई वर्ग के लिए एक अलग एक्सचेंज की आवश्यकता महसूस की है। 20 से अधिक देश अलग एसएमई बाजार संचालित करते हैं।

सवालों के घेरे में प. बंगाल का पंचायत चुनाव

जे के सिंह

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव 8 जुलाई को होना है। तारीख तो तय है, पर लोगों के जेहन में कई सवाल उठ रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के दौरान हुई हिंसा में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वजह से लोग आतंकित हैं। जाहिर है कि ऐसे में पहला सवाल यह है कि इस चुनाव में और कितनी लाशें गिरेंगी। राज्यपाल और राज्य चुनाव आयुक्त के बीच टकराव के कारण सवाल है कि क्या पंचायत चुनाव निर्धारित तारीख को हो पाएंगे? हाईकोर्ट में मामला दायर होने के कारण यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो गया है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा और इसमें लोगों के मारे जाने की कई दशक पुरानी परंपरा है। अभी तक नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी करने में ही 10 लोगों की हत्या हो चुकी है। एक नजर डालते हैं पिछले आंकड़ों पर। 2003 में 70, 2008 में 36, 2013 में 39 और 2018 में 40 लोगों की हत्या हुई थी। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 2003 में 70 लोग मारे गए थे। इसकी वजह यह थी कि उस दौरान विपक्ष मजबूत था। इस बार भी विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच कड़ा मुकाबला है, इसलिए संभावित मौत का आंकड़ा लोगों को सता रहा है। इस बार पंचायत चुनाव में करीब 76 हजार सीटों पर चुनाव होना है और 20585सीटों पर विपक्ष के उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल ही नहीं करने दिया गया है। हालांकि 2018 में तो करीब 34 फीसदी सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार बगैर किसी मुकाबले के चुनाव जीत गए थे। इस बार भाजपा के 57 हजार, वाममोर्चा के 49 हजार और कांग्रेस के 18 हजार उम्मीदवार चुनावी मैदान में मौजूद हैं। इस कड़े मुकाबले के कारण ही आम लोगों में खौफ है। शांत और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के मामले में चुनाव आयुक्त की भूमिका ही सवालों के घेरे में है। आयोग ने केंद्र सरकार से चुनाव के दौरान 22 कंपनी सेंट्रल फोर्स देने की मांग की थी, यानी बंगाल के 23 जिलों के लिए सेंट्रल फोर्स के कुल 17 सौ जवानों की मांग की गई थी। भाजपा और कांग्रेस की तरफ से पंचायत चुनाव के दौरान सेंट्रल फोर्स तैनात किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई है। चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनवाई के बाद आदेश दिया था कि राज्य के सात संवेदनशील जिलों में चुनाव के दौरान सेंट्रल फोर्स तैनात की जाए। इस पर अमल करने की बजाय राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए वापस हाईकोर्ट में भेज दिया। इसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि बंगाल के सभी जिलों में सेंट्रल फोर्स तैनात की जाए और उनकी संख्या 2013 के पंचायत चुनाव के मुकाबले अधिक होनी चाहिए। चीफ जस्टिस के आदेश का पालन नहीं हुआ तो चुनाव आयोग के खिलाफ कंटेंप्ट का मामला दायर कर दिया गया है। चुनाव आयुक्त को जवाब देने का आदेश दिया है। इसकी सुनवाई 28 जून को होनी है। केंद्र सरकार ने सेंट्रल फोर्स की 300 से अधिक कंपनियों को पश्चिम बंगाल में भेज दिया है और 500 कंपनियों का अभी बाकी है। सरकार की तरफ से पैरवी करते हुए एडीशनल सॉलीसीटर जनरल ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का हवाला देते हुए कहा है कि अगर 2013 के मॉडल पर पंचायत चुनाव कराया जाता है तो केंद्र सरकार को सेंट्रल फोर्स देने में सहूलियत होगी। इसके अलावा 2013 में पांच चरणों में चुनाव कराए गए थे। इस बार तो एक ही दिन चुनाव कराए जाने की योजना है, इसलिए संशय बना हुआ है कि क्या 8 जुलाई को पंचायत चुनाव हो पाएंगे? अगर हाईकोर्ट 2013 के मॉडल का हवाला देते हुए पंचायत चुनाव कराए जाने का आदेश देता है तो क्या होगा? इधर, अंतिम सवाल है कि राज्यपाल ने राज्य सरकार की सिफारिश पर राजीव सिन्हा को चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है। इसके बाद से ही पंचायत चुनाव को लेकर राज्यपाल और चुनाव आयुक्त बीच जबरदस्त टकराव बना हुआ है। राज्यपाल ने राज्य चुनाव आयुक्त की ज्वाइनिंग रिपोर्ट को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है। इस वजह से उनके अपने पद पर बने रहने की वैधानिकता को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। इस बाबत हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। अगर उनकी नियुक्ति अवैधानिक हो जाती है तो उनकी तरफ से चुनाव के लिए जारी अधिसूचना वैधानिक कैसे हो सकती है। इस लिहाज से पचायत चुनाव के लिए 28 जून की तारीख बेहद अहम है।

वोटों के गणित में पीडीए से आगे एनडीए

अजय सेठिया

विपक्षी दलों का जुटान हो गया, पटना में 15 दलों की बैठक हुई। इन सत्रह दलों की लोकसभा में 154 सीटें हैं और 2019 में इन्हें कुल मिला कर 38 प्रतिशत वोट मिला था। वहीं, भाजपा को अकेले 437 पर 37.36 प्रतिशत वोट और 303 सीटें मिलीं थी, भाजपा ने 105 सीटें अपने सहयोगियों के लिए छोड़ दी थीं, जिन्हें 7.7 प्रतिशत वोट और 50 सीटें मिलीं थी। यानि कुल 45 प्रतिशत वोट और 353 सीटें। इनमें जनता दल यू को 1.46 प्रतिशत वोट और 16 सीटें मिलीं थी और शिवसेना को 2.10 प्रतिशत वोट और 18 सीटें मिलीं थीं। यानि 2019 के चुनाव नतीजों के वाद जेडीयू और शिवसेना 34 लोकसभा सीटों और 3.56 प्रतिशत वोटों के साथ एनडीए से बाहर हो गए। लेकिन यह जमीनी सच्चाई नहीं है, शिवसेना और जेडीयू दोनों ही टूट चुके हैं, शिवसेना का लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, सभी शिंदे गुट में जा चुके है, जो एनडीए का हिस्सा है।

जनता दल यू के आधे से ज्यादा सांसद चुनाव आते आते पार्टी छोड़ कर अलग होने की तैयारी में हैं। इस समय बिहार में जो जेडीयू-आरजेडी-कांग्रेस गठबंधन बना है, वह गठबंधन 2014 के चुनाव में भी था, तब आरजेडी को 4, जेडीयू को 2, कांग्रेस को 2 और एनसीपी को एक सीट मिली थी। जबकि एनडीए को 31 सीटें मिली थी, जिनमें से भाजपा को 22, उसकी सहयोगी लोजपा को 6 और अन्य सहयोगी रालोसपा भी तीन सीटें जीत गई थी। 2019 में जेडीयू की ताकत भाजपा के साथ गठबंधन के कारण ही बढ़ी थी।

2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 31 प्रतिशत वोटों के साथ 282 सीटें मिलीं थी। 2019 में वोट शेयर 37.36 प्रतिशत हो गया और सीटें बढ़ कर 303 हो गई थीं। वोट प्रतिशत तो 6.36 प्रतिशत बढ़ा, लेकिन सीटें सिर्फ 21 बढ़ा। भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ने का मुख्य कारण यह था कि जहां 2014 में भाजपा ने 116 सीटें दो लाख वोटों से ज्यादा अंतर से जीती थी, वहीं 2019 में यह संख्या बढ़कर 164 हो गई। इसी तरह तीन लाख, चार लाख, पांच लाख वोटों से जीतने वाली सीटों में भी बढ़ोतरी हुई थी। इससे वोट प्रतिशत तो बढ़ गया, लेकिन उस मुकाबले में सीटें उतनी नहीं बढीं। देश में मोदी सरकार के खिलाफ ऐसी कोई हवा भी नहीं चल रही कि इन 164 सीटों पर बड़ा उलटफेर हो जाएगा। विपक्षी गठबंधन से मीडिया में नेरेटिव जरुर बनता है, जमीन पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा का महागठबंधन होने के बावजूद 80 में से 64 लोकसभा सीटें जीतीं थीं। जबकि बसपा से गठबंधन के बावजूद सपा सिर्फ पांच सीटें जीत पाईं, इनमें से दो सीटें उपचुनाव में हार गई, क्योंकि बसपा से गठबंधन टूट गया था।

समाजवादी पार्टी ने 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके भी चुनाव लड़ कर देख लिया है। इसलिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से गठबंधन करके तभी फायदा हो सकता है, अगर यूपी का सारा मुस्लिम वोट मायावती का साथ छोड़कर उनके साथ आ जाए। ऐसी संभावना बन भी रही है। इसी संभावना को देखते हुए ही अखिलेश यादव ने गठबंधन का रूख किया है, लेकिन ऐसी सूरत में भी पिछली बार मुस्लिम-दलित गठबंधन के चलते 10 सीटें जीतने वाली मायावती को नुकसान होगा, भाजपा को नहीं। गठबंधन का नाम देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन (पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक एलायंस) रखा जा रहा है। इस नाम का खुलासा बहुत छोटे से दल सीपीआई (एमएल) ने किया है, आधिकारिक तौर पर इसका एलान अभी नहीं किया गया है। इन तीनों शब्दों पर गौर करिए। पहला शब्द खुद का बचाव करने वाला है, क्योंकि विपक्षी नेताओं, खासकर राहुल गांधी की देशभक्ति पर भाजपा के नेता सवाल उठाते रहते हैं। दूसरा शब्द लोकतांत्रिक इसलिए है, क्योंकि विपक्ष का सारा नेरेटिव ही यह है कि मोदी के रहते लोकतंत्र खतरे में है और वे ही लोकतंत्र को बचा सकते हैं। लेकिन जब तक उस नेरेटिव से जनता न जुड़े, तब तक नेरेटिव बना देने से न तो कोई चुनाव हार सकता है, न जीत सकता है।

हम जमीनी हकीकत को देखें, तो 2019 में नौ राज्यों मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की 199 लोकसभा सीटों में से 180 सीटें एनडीए जीती थी, जिनमें से 177 उम्मीदवार भाजपा के जीते थे और तीन सहयोगी। विपक्ष के 19 सांसदों में से दस बसपा के, पांच सपा के, चार कांग्रेस के (यूपी-1, मध्यप्रदेश-1, छतीसगढ़-2) जीते थे। उत्तर प्रदेश और दिल्ली को छोड़कर बाकी सभी सात राज्यों में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं, यानि किसी अन्य पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। उत्तर प्रदेश में भाजपा गठबंधन ने 80 में से 64 और दिल्ली की सभी सात सीटें जीती थीं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों का विभाजन नहीं हुआ था क्योंकि दोनों बड़ी पार्टियां सपा-बसपा मिलकर चुनाव लड़ी थीं। मायावती और अखिलेश यादव के गठबंधन के बावजूद अगर विपक्ष 16 पर अटक गया था तो अब क्या उम्मीद की जा सकती है, जब मायावती भी गठबंधन के साथ नहीं है। दूसरी तरफ असुदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी मुस्लिम वोटों में विभाजन करने पहुंच रही है, और आम आदमी पार्टी भी भाजपा विरोधी वोटों को थोड़ा बहुत विभाजित करेगी ही। दिल्ली में पिछली बार भाजपा ने सभी सातों सीटें जीतीं थीं, कांग्रेस दूसरे नंबर पर और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी। इस बार भी यही स्थिति रहने की संभावना है। राजस्थान में भाजपा ने सभी 25 सीटें (नागौर की एक सीट भाजपा ने अपने सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को दी थी), मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें, छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें, गुजरात की सभी 28 सीटें जीतीं। हरियाणा की सभी दस, हिमाचल प्रदेश की सभी चार (जिनमें से एक उपचुनाव में हार गई थी) और उत्तराखंड की भी सभी पांच सीटें जीती थीं। इन सभी राज्यों में कांग्रेस के अलावा किसी अन्य विपक्षी दल का कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए इन राज्यों में कांग्रेस को किसी विपक्षी दल के सहयोग से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अलबत्ता आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ कर कांग्रेस को नुकसान पहुँचाने का काम जरुर करेगी, जैसे गुजरात विधानसभा चुनाव में किया।

2019 के लोकसभा चुनाव से छह महीने पहले मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव हुए थे। तीनों ही राज्यों में भाजपा हारी थी, लेकिन लोकसभा चुनावों में इन तीनों राज्यों की 65 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 3 सीटें जीत सकी थी। इन तीनों ही राज्यों में इसी दिसंबर में विधानसभा चुनाव हैं। राहुल गांधी ने पटना में दावा किया है कि कांग्रेस तीनों राज्य जीतेगी, वह जीत भी जाए, तो भी उसका लोकसभा चुनावों पर कोई असर नहीं होगा। क्योंकि विपक्षी दलों का जुटान भले ही हो जाए, विपक्षी दलों की जनता में अपील नहीं है। विपक्ष में जनता का भरोसा तभी होगा, जब जनता का मोदी से मोह भंग होगा। विपक्ष जनता को डराने की कोशिश कर रहा है कि अगर मोदी 2024 में भी जीत गए, तो फिर कभी चुनाव नहीं होंगे। लेकिन जनता में यह डर तब तक पैदा नहीं होगा, जब तक उसका मोदी से मोह भंग न हो। अलबत्ता कश्मीर से 370 हटाना और रामजन्मभूमि मन्दिर निर्माण जैसे कई कारण हैं, जिनसे मोदी के प्रति आस्था में बढ़ोतरी की संभावना है। विपक्ष को भी इस बात का एहसास है, इसलिए उसकी पटना में साझा रैली करने की हिम्मत नहीं हुई।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

चतुर्वेदोपनिषद्

यह एक लघुकाय उपनिषद् है। इसमें चारों वेदों के प्राकट्य का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। सर्वप्रथम सृष्टि के शुभारम्भ का उल्लेख है। उसी क्रम में ध्यानावस्थित ब्रह्माजी के चारों मुखों से जो कि चारों दिशाओं में अवस्थित थे, क्रमशः व्याहृतियाँ, छन्द एवं वेद प्रकट होने का उल्लेख है। तत्पश्चात् विराट् पुरुष के व्यापक स्वरूप का चित्रण किया गया है। अन्त में इस उपनिषद् के पारायण की फलश्रुति बताई गई है।अब इस महान् उपनिषद् (चतुर्वेदोपनिषद्) के सम्बन्ध में प्रकाश डाला जाता है। सृष्टि से पूर्व सर्व प्रथम एक मात्र नारायण ही थे न ब्रह्मा और न ही ईशान (शिव) थे। इनके अतिरिक्त पृथ्वी, वायु, आकाश, नक्षत्र एवं सूर्य आदि में से कोई नहीं था। वह एक मात्र अकेला %नर% (विराट् पुरुष) ही था। ध्यान में स्थित तपस्यारत उस नर (विराट् पुरुष) के ललाट (मस्तक) से स्वेद (पसीना) गिरा। वही यह आपः (जल) हुआ। वही यह (आप) हमारे लिए हिरण्यमय अन्न रूप है और उससे ही चार मुख वाले ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। उस (ब्रह्मा) ने ध्यानावस्था में पूर्वाभिमुख होकर %भूः% व्याहृति, गायत्री छन्द, ऋग्वेदः पश्चिमाभिमुख होकर भूः व्याइति, त्रिष्टुप् छन्द एवं यजुर्वेद; उत्तराभिमुख होकर भुवः व्याहृति, जगती छन्द एवं सामवेद तथा अन्त में दक्षिणाभिमुख होकर जनत (सम्भवतः जनः) व्याहृति, अनुष्टुप् छन्द एवं अथर्ववेद को प्रकट किया।

वे अविनाशी देव (विराट् पुरुष) जिनके कि सहस्रों सिर एवं सहस्रों नेत्र हैं। सम्पूर्ण विश्व को प्रादुर्भूत करने वाले वे परमदेव हमेशा सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। (वे देव) नारायण एवं हरि आदि शब्द से भी प्रख्यात हैं। उन ऋषि स्वरूप सम्पूर्ण जगत् के स्वामी समुद्रशायी विश्व-रूप परम विराट् पुरुष का आश्रय प्राप्त करके ही यह संसार जीवित जाग्रत है। (यह विराट् पुरुष) कमल कोश के समान हृदय में अधोमुख होकर एक कोश के रूप में लटका है, जो अपनी शक्तियों से ही सभी कुछ करता रहता है। उसके मध्य में श्रेष्ठ अनि स्थित है, जिसकी ज्वाला चारों ओर मुखवाली अर्थात् लपकने वाली हैं। उसके मध्य में ही वह्निशिखा है, जो अणीय के ऊपर प्रतिष्ठित है। उस श्रेष्ठ शिखा के मध्य में ही वह विराट् पुरुष परब्रह्म स्थित है। वह ही ब्रह्मा, शिव, अक्षर (ब्रह्म) तथा परम प्रभु स्वयं प्रकाश रूप है । **क्रमशः**

एक पुल ने बदल दिए जिंदगी के मायने

राजेश दामोदर काची

डेंगले पुल के पास जब मैंने पहली बार नदी में किसी डूबते को बचाया था, तब मेरी उम्र उन्नीस साल थी। वह बच्ची गलती से पुल से नीचे नदी में गिर गई थी। बच्ची को बचाने के बाद उसका परिवार मुझे धन्यवाद कहने मेरे घर आया। उन लोगों की आँखों में झलकती खुशी और उनका आशीर्वाद मेरे लिए अभूतपूर्व इनाम था। उसी पल मैंने तय कर लिया था कि मैं जिंदगी भर ऐसे इनामों के लिए ही जीऊँगा।

मैं पुणे के शिवाजीनगर में रहता हूँ। मैं उसी डेंगले पुल के पास स्ट्रीट फूड की दुकान चलाता हूँ। मुझे दुकान चलाते हुए दो दशक से ज्यादा समय बीत गया है। इस दौरान सैकड़ों मौके आए जब मैंने लोगों को नदी में डूबने से बचाया। ये लोग कई बार तो दुर्घटनावश नदी में गिरते हैं, तो कई मामले आत्महत्या की कोशिश से जुड़े होते हैं। लोगों को बचाते-बचाते मैं आसपास के इलाकों में %रक्षक राजू% के नाम से प्रसिद्ध हो गया हूँ। डेंगले पुल ही नहीं, आस-पड़ोस में कहीं भी यदि कोई डूब रहा होता है, तो लोग सबसे पहले मुझे ही इत्तिला करते हैं। यहाँ तक कि कई दफे पुलिस ने भी मुझसे मदद ली है। मेरा काम डूब रहे लोगों को पानी से निकालने तक ही सीमित नहीं है। मैं इन लोगों को पास के अस्पताल तक ले जाता हूँ। इनके परिवार वालों को स्थिति के बारे में तत्काल सूचित करता हूँ। कई बार ऐसा होता है, जब व्यक्ति के संबंधी उस तक पहुँचने में एक-दो दिन का वक्त लगा देते हैं। इस स्थिति में मुझे ही मरीज की देखरेख करनी होती है, जब तक कि वह पूरी तरह ठीक न हो जाए। हालांकि यह नौबत कभी-कभार ही आती है। 1997 और 2004 के बीच मैंने सबसे ज्यादा लोगों को बचाया, क्योंकि उस दौरान पुणे और आसपास के इलाकों ने भारी बारिश का दंश झेला है। नदी के किनारों पर बसे इलाके बाढ़ की वजह से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। सबसे ज्यादा पेरशानी बच्चों-बूढ़ों ओर निःशक्तों को हुई थी। मैंने इन

लोगों को सुरक्षित स्थानपर पहुँचाने में प्रशासन की मदद की थी। दशकों बीत जाने के बावजूद मैं अब भी पानी में उतरने से पहले नहीं सोचता। मेरा शरीर पूरी तरह फिट है। मैंने कभी तंबाकू, सिगरेट या शराब का सेवन नहीं किया। तैरना और अभ्यास मेरी दिनचर्या में शामिल हैं। तीन बच्चों समेत पाँच सदस्यों का मेरा परिवार मुझे इस नेक काम में पूरी तरह मदद करता है। कई ऐसे मौके आए हैं, जब दूसरों को बचाते हुए मेरी खुद की जिंदगी जोखिम में पड़ गई। एक अस्सी साल की वृद्धा को डूबने से बचाने में मुझे बहुत मुश्किल हुई। जब मैं उसे बाहर ला रहा था, तो उसने मुझे कसकर गले लगा रखा था। जैसे-तैसे ही मै तैरकर बाहर आ सका था। मेरे काम से प्रभावित होकर पुलिस ने मुझ पर एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। उनकी मदद करते हुए साढ़े चार सौ से ज्यादा शवों को भी मैं पानी से निकाल चुका हूँ। इस काम में कई बार मेरा सामना ऐसी लाशों से भी हुआ है जो पूरी तरह सड़ चुकी होती हैं। ऐसी स्थिति में मुझसे कुछ दिनों तक खाना नहीं खाया जाता, पर पुलिस के अगले बुलावे पर मेरे मुँह से यही निकलता है, मैं तुरंत आ रहा हूँ। मेरे दोस्त मुझे सलाह देते हैं कि पागलों की तरह नदी में उतरने के वजाय मुझे दुकान पर ध्यान देना चाहिए। पर मुझे यही लगता है कि मैं अपने काम पर अच्छी तरह ध्यान दे रहा हूँ।

झूठ से भरी है ओबामा की टिप्पणी

अनिल त्रिगुणायत

बराक ओबामा अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने बतौर राष्ट्रपति दो बार भारत की यात्रा की। वह भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली अमेरिका यात्रा के समय भी वही राष्ट्रपति थे। ऐसे में ओबामा ने जब भारत के अल्पसंख्यकों के बारे में टिप्पणी की है, तो उन्हें अच्छी तरह से पता है कि क्या सच है और क्या झूठ। दरअसल, अमेरिका में बहुत पहले से मानवाधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार जैसे मुद्दों को लेकर दूसरे देशों को नीचा दिखाने वाला एक कूटनीतिक टूलकिट सक्रिय रहा है। हालांकि, वे अपने देश के बारे में नहीं बोलना चाहते जहां लोकतंत्र, धर्म और नस्ल को लेकर काफी भेदभाव होता है। मगर वे दूसरे देशों के बारे में टिप्पणियां करते रहते हैं।

दरअसल, भारत का विरोध करने वाले पाकिस्तान, चीन तथा तुर्की जैसे देशों के हितों के लिए काम करने वाले समूहों को भारत के बारे में ऐसी बातों को उछालना अच्छा लगता है। अमेरिका में राजनीति प्रेशर ग्रुप्स या दबाव समूहों पर निर्भर करती है। वहां कई तरह के समूह काम करते हैं, जिनमें से किसी को पाकिस्तान से फंड मिलता है तो किसी को चीन से या किसी को किसी और से। उनकी अपनी प्रचार एजेंसियां होती हैं। ऐसे में, जब भारत या दूसरे देशों के नेता यूरोप या पश्चिमी देशों के दौरे करते हैं तो वह कोई-न-कोई मुद्दा खोज लेते हैं। अगर कोई मुद्दा नहीं हो, तो वे कोई मुद्दा गढ़ लेते हैं। उनका पूर्णकालिक काम ही ऐसी चर्चाओं को छेड़ने की कोशिश करते रहना होता है। ये उनकी एक रणनीति होती है कि वे पहले ही से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। अधिकतर देश घबरा जाते हैं मगर, भारत दूसरे देशों जैसा नहीं है।

अमेरिका की मौजूदा बाइडेन सरकार भारत के साथ रिश्ते और अच्छे बनाना चाहती है। वह भारत को एक वैश्विक रणनीति में साझीदार बनाना चाहती है। वे इस बात को समझते हैं कि भारत में किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी संसद कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन में और मीडिया के साथ संवाद करते हुए भी पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि सरकार की ओर से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। और हमने देखा कि अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर अमेरिका के दोनों ही दलों - डेमोक्रेट और रिपब्लिकन - ने समर्थन दिया। यानी, अमेरिका के भीतर, और बाकी दुनिया भी जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया है, और भारत की सोच क्या है।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका के सबसे बड़े थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने भारत के मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के बारे में अपनी एक रिपोर्ट में बताया, कि भारत के 98 फीसदी मुसलमान मानते हैं कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता। यानी, अमेरिका की अपनी ही एजेंसी ओबामा की बातों से अलग रिपोर्ट करती है, मगर उसकी चर्चा नहीं होती क्योंकि उससे उनका मकसद पूरा नहीं होता। भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर, भारत के बारे में किसी को भी टिप्पणी करते समय तथ्यों को अच्छी तरह से जांच लेना चाहिए। हालांकि, यह भी संभव है कि अमेरिका में अंदरूनी तौर पर कोई सहमति हो गयी हो कि मौजूदा राष्ट्रपति की जगह, कोई पूर्व राष्ट्रपति ऐसी कोई बात कह दे जिससे कि इस बारे में बहस छिड़ जाए।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात में आंतरिक तौर पर भारत के अल्पसंख्यकों के बारे में चर्चा भी की हो। बाइडेन ने संवाददाता सम्मेलन में कहा भी कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात में लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में अच्छी चर्चा हुई। असल में, शीर्ष नेताओं की बातचीत में इस तरह की चर्चा एक औपचारिक प्रक्रिया का हिस्सा होती है। मगर उसे खुलकर प्रकट करना अलग बात है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सरकारें दोहरी रणनीति अपनाती हैं, जिसमें सरकार किसी और माध्यम से अपनी बात भी कहलवा लेती है, और द्विपक्षीय स्तर पर मुलाकात से अपने उद्देश्य भी पूरे कर लेती है। यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि ओबामा के संबंध प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी बहुत अच्छे हैं।

कुल मिलाकर, भारत को इन घटनाओं को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। जब भी ऐसे प्रयास हों तो भारत को उन्हें आईना दिखाकर बताना चाहिए कि उनके अपने देश की सच्चाई क्या है। भारत में मुसलमान हों या कोई भी अल्पसंख्यक, उन्हें बराबरी के अधिकार हैं। सामाजिक स्तर पर थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं, मगर सरकारी योजनाओं में उन्हें भी पूरा हिस्सा मिलता है और कोई भेदभाव नहीं किया जाता। और ये बात भारत को बताते रहना चाहिए। विदेश मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओबामा की टिप्पणी का यह जवाब देकर बिलकुल सही किया, कि अमेरिका और उनके सहयोगियों ने ओबामा के ही कार्यकाल में छह मुस्लिम-बहुल देशों पर बम बरसाए। उन्होंने ये भी गिनाया कि ओबामा के समय हुए हमलों से कहां और कितने लोगों की मौत हुई। तो एक तरफ ओबामा भारत पर टिप्पणी कर मुसलमानों का पक्ष लेते हुए दिखना चाहते हैं और दूसरी तरफ उन्होंने ही मुस्लिम देशों का ये हाल कर दिया।

अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों के बाद जो आतंक विरोधी कानून बनाये गये, उनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल मुसलमानों के ही विरुद्ध हुआ। तो भारत की प्रतिक्रिया बिलकुल जायज है। मगर, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भारत के साथ समस्या नहीं है। लेकिन दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं होता जहां कोई समस्या नहीं हो। चाहे लोकतंत्र हो या शासन की कोई और व्यवस्था, उन सबमें कोई ना कोई कमी होती है। अब भारत दुनिया में मुस्लिम आबादी वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। दुनिया में कौन सा ऐसा देश है, जहां दिग्गज कलाकार मुस्लिम समुदाय से हैं, जहां दो-दो मुस्लिम राष्ट्रपति हुए, एक उपराष्ट्रपति हुआ, मुख्य न्यायाधीश हुआ, सेना, खुफिया संगठनों के प्रमुख हुए। दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यक इतने शीर्ष पदों तक पहुंचते हैं। ऐसे में यदि कोई भेदभाव को लेकर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसका जवाब देने के लिए संवाद की एक रणनीति बनायी जानी चाहिए। उसके जरिए सच बताया जाना चाहिए और प्यू रिसर्च सेंटर के शोध जैसे तथ्यों का उल्लेख करना चाहिए जिसमें भारत के 98 फीसदी मुसलमानों ने बताया कि उनके साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। ऐसे में कोई नयी बात कहां से खड़ी हो सकती है।

बापू की दिनचर्या

विश्राम (भाग-2)

गतांक से आगे...

भोजन के अनंतर बापू के विश्राम की वेला थी। संभवतः मीरा बहन हलके हाथों उनके पाँवों की मालिश कर रही थीं। बापू की पलकें झपकने के निकट थीं। जैनेंद्रजी बोले- आपका विश्राम का समय है, नींद में मैं बाधक न बनूँगा, चलूँ। बापू बोले-नहीं, बाधक न बनोगे। नींद अपने समय से आ जाएगी। आने पर तुम समझ ही जाओगे। तब चाहो तो उठ जाना। जैनेंद्रजी का कथन है-और, मेरे देखते-देखते चंद सैकंडों में नींद चुपचाप चली आई। शिशुवत् वे सो गए और मैं अचंभे में पड़ गया। नींद भी इस तरह किसी की चेरी हो सकती है, यह मैं संभव न मानता था। लगभग तभी मीरा बहन के हाथ रुक गए। समझ गया, नींद समय से आई है। समय होने पर उसे उसी तरह चले जाना होगा। बापू की ओर से उस बेचारी का भी समय नियुक्त था! दिन के विश्राम को बापू कितना महत्त्व देते, इसका उदाहरण एक अन्य घटना से मिलता है। बात सन् 1939 की है और गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर से संबंधित है। अप्रासंगिक होते हुए भी प्रासंगिक है। गुरुदेव उन दिनों अस्वस्थ थे। चिकित्सकों ने उनको पूर्ण विश्राम की सलाह दी, किंतु वे अपने सारे काम नित्य नियमपूर्वक करते रहते। इस कारण शांतिनिकेतन के कुछ सज्जनों ने बाप को तार देकर बुलाया। बापू पहुँचकर गुरुदेव से मिले और बोले- मैं आपसे भिक्षा चाहता हूँ। गुरुदेव बोले- भिक्षुक भला क्या भिक्षा दे सकता है? लेकिन बापू टस से मस न हुए, उन्होंने गुरुदेव को वचनबद्ध करा लिया। बोले—भोजन के पश्चात् आपको एक घंटा पूर्ण विश्राम करना होगा। कविगुरु को विवश होकर बापू की बात माननी पड़ी। कुछ दिनों बाद आचार्य क्षितिमोहन सेन गुरुदेव से मिलने पहुँचे। गुरुदेव ने तुरंत भोजन किया था। वे कमरे के सारे दरवाजे बंद कर लेटे थे। दरवाजे की दरार से कुछ प्रकाश झलक रहा था। हलचल से गुरुदेव ने आचार्य सेन को पहचान लिया। प्रश्न किया-ठाकुर दा हैं क्या? आचार्य सेन ने हाँ कहते हुए आश्चर्यचकित होकर उनसे प्रश्न किया— आप भीतर कर क्या रहे हैं? गुरुदेव का सहज उत्तर था-गांधीजी को भिक्षा दे रहा हूँ। ऐसे थे बापू और ऐसी थी उनके विश्राम की चमत्कारी चर्या!

संक्षिप्त समाचार

स्वशासी बजट में रिसर्च हेतु बजट प्रावधान करने संभाग आयुक्त के निर्देश

रायपुर। रायपुर संभाग आयुक्त डॉ. संजय कुमार अलंग की अध्यक्षता में आज पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय और डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय के स्वशासी समिति की प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों के मजदूरी एवं वेतन, मानदेय, मशीन उपकरण/केमिकल कंज्यूमेबल, मशीनरी रखरखाव, लाइब्रेरी जर्नल्स, हॉस्टल संबंधी व्यय, लैब एवं ऑफिस फर्नीचर, फायर फाइटिंग, लघु निर्माण कार्य तथा झूला घर जैसे विषयों के बजट प्रावधान पर मदवार चर्चा की गई। चर्चा उपरांत वित्तीय वर्ष 2023-24 के स्वशासी बजट का अनुमोदन भी किया गया। डॉ. संजय अलंग ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबंधित अस्पताल में स्टाफ नर्स एवं अन्य रिक्त पदों पर भर्ती हेतु कार्यालय स्तर पर तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने चिकित्सा महाविद्यालय के 2023-24 के स्वशासी बजट में रिसर्च हेतु बजट प्रावधान करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ. विष्णु दत्त, स्वशासी समिति की मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता डॉ. तृप्ति नागरिया, अम्बेडकर अस्पताल के संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक डॉ. एस. बी. एस. नेताम, सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. मंजू सिंह, संयुक्त संचालक वित्त सुषमा ठाकुर, विभागाध्यक्ष ईएनटी डॉ. हंसा बंजारा, एसीआई के कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. स्मित श्रीवास्तव, प्रशासनिक अधिकारी अम्बेडकर अस्पताल रंजना ध्रुव, सीटीवीएस विभागाध्यक्ष डॉ. कृष्णकांत साहू, प्राचार्य फिजियोथेरेपी महाविद्यालय डॉ. रोहित राजपूत, स्व. बिन्नी बाई सोनकर के प्रतिनिधि श्री कृष्ण कुमार सोनकर समेत लोक निर्माण विभाग के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

मूसलाधार बारिश से शिवनाथ उफान पर देखने उमड़ा लोगों का हुजूम

राजनांदगांव। पिछले चार दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण इन दिनों शिवनाथ नदी उफान पर है। शिवनाथ के अलावा अन्य सहायक नदियों की रफ्तार भी बढ़ गई है। खेतों में किसानों के लिए बुआई के बाद अब तक हुई बारिश फायदेमंद साबित होगी। शिवनाथ नदी के उफान पर चलने से उसे देखने, वीडियो और फोटो बनाने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। रविवार से रूक-रूककर व झमाझम बारिश के चलते जिले समेत शहरी इलाकों में लोगों की दिनचर्या जहां प्रभावित हुई है वहीं शहरी क्षेत्र के निचली बस्तियों में नालियों का गंदा पानी घरों व रास्तों में आने से बदबू और गंदगी फैलने लग गया है। इसके अलावा जिला अस्पताल, तहसील कार्यालय समेत अन्य स्थानों में बारिश का पानी भर गया है। रविवार से शुरू हुए बरसात के कारण शिवनाथ का जलस्तर तेज हो गया है। पुराना पुल और नया एनीकट भी नदी के जलस्तर बढने से डूब गया है। इसके चलते नदी किनारे के गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। शिवनाथ नदी के उफान पर चलने को लेकर लोग शिवनाथ तट पर पहुंचने लगे हैं।

आकाशीय बिजली गिरने से 5 पुलिसकमी घायल

मनेन्द्रगढ़। जनकपुर थाना में बुधवार की दोपहर अचानक आकाशीय बिजली गिरने से 5 पुलिस कर्मी मामूली रूप से घायल हो गए, जबकि थाने में लगा वायरलेस और कम्प्यूटर सेट पूरी तरह खराब हो गए। इस घटना से पुलिस महकमे में हडकंप मच गया। बुधवार की दोपहर करीब ढाई बजे तीव्र गर्जना के साथ आकाशीय बिजली सीधे जनकपुर थाना परिसर में आ गिरी। ड्यूटी पर तैनात प्रधान आरक्षक धीरेन्द्र सिंह, राजाराम, सुनील रजक, आरक्षक रघुनंदन एवं महिला आरक्षक प्रियंका पांडेय व प्रीति बिंदु मिंज इसकी चपेट में आकर मामूली रूप से घायल हो गए। महिला आरक्षक प्रियंका पांडेय को घटना के बाद से कानों में सुनाई कम पड़ रहा है। सभी पुलिसकर्मियों का उपचार किया जा रहा है, वहीं थाने में आकाशीय बिजली के गिरने से वायरलेस और कम्प्यूटर सिस्टम भी पूरी तरह से खराब हो गए हैं। ज्ञात हो कि एक दिन पहले मंगलवार को जनकपुर में अलग-अलग स्थानों में आकाशीय बिजली गिरने से जहां 2 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं गंभीर रूप से घायल 2 लोग अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं।

सुकमा में नक्सलियों ने उपसरपंच का किया अपहरण, आधिकारिक पुष्टि नहीं

सुकमा। नक्सलियों ने बुर्कापाल पंचायत के उपसरपंच का अपहरण किया है। जिसके बाद ऐसा लगने लगा है कि बस्तर में नक्सलियों का खौफ बरकरार है। सरकार और पुलिस भले ही लाख दावे करें, लेकिन कुछ इलाकों में नक्सलियों का खौफ अब भी बरकरार है। नक्सली बड़ी आसानी से वारदात को अंजाम देते हैं और घने जंगलों में पनाह ले लेते हैं। नक्सली इसके साथ ग्रामीणों को अगवा करने, वसूली करने के साथ सामानों की तस्करी करने में भी माहिर हो चले हैं। पुलिस समय-समय पर नक्सलियों का नेटवर्क तोड़ती तो है, लेकिन कुछ दिनों बाद नक्सली नया नेटवर्क बनाकर काम में जुट जाते हैं। वहीं नक्सली मुखबिरी के शक में किसी की हत्या करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। सुकमा जिले के बुर्कापाल पंचायत के उपसरपंच माड़वी गंगा को नक्सलियों ने अगवा कर लिया है। नक्सलियों ने माड़वी गंगा को उसके घर से अगवा किया। चश्मदीदों के मुताबिक माड़वी को अगवा करने के लिए दर्जन भर से ज्यादा नक्सलियों ने गांव में घेराबंदी की थी।

दिल्ली में छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस की बैठक, चुनाव की रणनीति पर चर्चा

अपनी उपलब्धियों पर लड़ेंगे चुनाव : शैलजा

दिल्ली/रायपुर। छत्तीसगढ़ में साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने है। सत्तारूढ़ कांग्रेस अभी से ही इसकी तैयारी में जुट गई है। आज दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने बुधवार को छत्तीसगढ़ में पार्टी की रणनीति और चुनाव तैयारियों पर चर्चा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा राज्य में पार्टी की प्रभारी कुमारी शैलजा और महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में शामिल हुए।

बैठक के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि राज्य सरकार की उपलब्धियां, भाजपा की नकारात्मक सोच के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जोड़ने की विचारधारा को लेकर हमारे कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे। मल्लिकार्जून खरगे ने अपना मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाजपा के पास धर्म के अलावा कोई एजेंडा नहीं है जबकि हमारा एजेंडा काम और हमारी विचारधारा है।

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य नवंबर-दिसंबर में होने वाले छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए योजना तैयार करना है। हमारे पास फिर से सरकार बनाने का अच्छा मौका है। हम कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास काम करने का एक तरीका है, उसकी नीतियां और उद्देश्य हैं। पिछला चुनाव सामूहिक नेतृत्व के आधार पर लड़ा गया था। सबसे अच्छा है कि हम सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ें, टीम का नेतृत्व कोई भी कर सकता है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए खरगे ने कहा कि पार्टी के सदस्य छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए मिलकर काम करेंगे। खरगे ने एक ट्वीट में कहा, ''गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ये हमारे लिए केवल कोई नारा नहीं है, छत्तीसगढ़ की उन्नति व सामाजिक न्याय के लिए एक ध्येय है। छत्तीसगढ़ की जनता और कांग्रेस पार्टी में उनका अटूट विश्वास, विकास की अविरल धारा को आगे बढ़ाता रहेगा।'' उन्होंने कहा, ''हम मिलकर काम करेंगे और छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में बदलाव लाते रहेंगे।'' बैठक के बाद बघेल ने ट्वीट किया, ''नवा छत्तीसगढ़ के मॉडल से जनता के जीवन में आ रहे बदलाव एवं आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अहम चर्चा हुई।'' इसके साथ ही उन्होंने 'हैं तैयार हम' का हैशटैग भी इस्तेमाल किया।

बैठक में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रमुख मोहन मरकाम और टीएस सिंह देव सहित अन्य कैबिनेट मंत्री भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि, पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है और बैठक में कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किए गए नवा छत्तीसगढ़ मॉडल के बाद लोगों के जीवन में बदलाव पर चर्चा हुई है।

प्रदेश के 43 हजार संविदा कर्मचारी तीन जुलाई से हड़ताल पर

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के 43 हजार संविदा कर्मी तीन जुलाई से हड़ताल पर जा रहे हैं। यह कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश में रथ यात्रा भी निकाली थी और कलेक्टर व विधायक को ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद भी शासन से कोई कदम नहीं उठाने पर अब हड़ताल का एलान कर दिया है। इसे लेकर कर्मचारियों ने बीजापुर में अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने जन घोषणापत्र में वादा किया था, लेकिन साढ़े चार साल होने के बाद भी पूरा नहीं किया। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने आंदोलन का एलान किया है। इससे पहले कर्मचारियों ने तीन हजार किलोमीटर की रथयात्रा निकाली थी और सभी 33 जिलों के कलेक्टर को ज्ञापन सौपा था। प्रांत अध्यक्ष कौशलेश तिवारी ने बताया कि सरकार ने संविदा कर्मचारियों से 2018 के चुनाव के जनघोषण पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में नियमितिकरण का वादा किया था। इसे इतने साल बीत जाने के बाद भी पूरा न करना गैर लोकतांत्रिक है। महासंघ के प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सिन्हा और अशोक कुर्रे ने बताया कि, कांग्रेस के कई बड़े नेता के अलावा सरकार के मुखिया के नाते मुख्यमंत्री विधानसभा में या अन्य मीडिया माध्यमों में नियमितीकरण की अपनी बात तो कहते हैं। आज तक इस पर किसी भी प्रकार का ठोस अमल नहीं किया गया। कहा कि, संविदा कर्मी की भीड़ 2024 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में किस पार्टी की सरकार बनेगी, यह तय करेगी। सरकार को सचेत होना चाहिए। जिला अध्यक्ष रमाकांत पुनेठा ने कहा कि इन साढ़े चार साल में सरकार की तरफ से संवादहीनता की स्थिति है।

पैरामेडिकल कोर्स के नाम पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ : जनता कांग्रेस

रायपुर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने शिक्षा को व्यवसाय बनाकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप पैरामेडिकल संस्थानों पर लगाया है। जनता कांग्रेस का दावा कि प्रदेश के कई जिलों के अंदर पैरामेडिकल कॉलेज संचालित हैं। जो बच्चों से एडमिशन के नाम पर मोटी फीस वसूल रहे हैं।लेकिन ना तो ऐसे संस्थानों में पढ़ाई होती है और ना ही बच्चों को कहीं प्लेसमेंट मिलता है। और तो और इन संस्थानों छत्तीसगढ़ में ऐसे कोर्स को संचालित करने का अधिकार भी नहीं प्राप्त है। ऐसे संस्थानों में इन संस्थानों में लैब अटेंडर, टैक्नीशियन, ड्रेसर, एक्स-रे टैक्नीशियन, ओटी टैक्नीशियन जैसे कोर्स का संचालन किया जा रहा है।

जनता कांग्रेस के प्रदीप साहू ने कहा पैरामेडिकल कोर्स के नाम पर छात्र-छात्राओं से मोटी फीस वसूली जा रही है। इसके साथ ही छात्रों को सरकारी नौकरी और पंजीयन देने का दावा भी किया जाता है। लेकिन अब तक ऐसी संस्थाओं में परीक्षाएं भी आयोजित नहीं की गई हैं। जिसके कारण छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य अधर में है।पैरामेडिकल संस्थाओं के नाम पर कोचिंग संस्थाएं और कुछ महाविद्यालय इसका संचालन कर रही हैं।उनके पास किसी प्रकार की अनुमति नहीं है। ये संस्थान अन्य राज्यों का प्रमाण पत्र देते हैं और पढ़ाई रायपुर में करवाई जाती है,एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट्स को दूसरे राज्य ले जाया जाता है।

नहीं हो रहीं परीक्षाएं आयोजित

पैरामेडिकल कोर्स के नाम पर संचालित हो रही संस्थानों में पिछले 5 वर्षों से परीक्षाएं भी आयोजित नहीं की गईं है। ऐसे में तंग आकर स्टूडेंट्स अपनी

पढ़ाई को अधूरा छोड़ रहे हैं और आत्महत्या करने पर भी मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से चल रहे पैरामेडिकल संस्थानों की जांच करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से शिकायत की गई है। इसके बावजूद अब तक इस मामले पर शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है।

कितने संस्थानों को है पैरामेडिकल कोर्स संचालन की अनुमति

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा से मिली जानकारी के मुताबिक प्रवेश पत्र 2022- 23 में छत्तीसगढ़ में सिर्फ 7 प्राइवेट संस्थाओं को पैरामेडिकल कोर्स संचालित करने की अनुमति दी गई है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में ऐसी सैकड़ों संस्थाएं हैं जो अवैध रूप से छत्तीसगढ़ में पैरामेडिकल कोर्स करवा रही है। अजीत जोगी युवा मोर्चा ने छत्तीसगढ़ सरकार से इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की है। इसके साथ ही अवैध रूप से संचालित हो रहे पैरामेडिकल संस्थानों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।

टोल प्लाजा पर कांग्रेसियों ने की तोड़फोड़

स्थानीय वाहनों से वसूली पर भड़के, 2 घंटे जाम रहा दुर्ग-नागपुर हाईवे

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में स्थानीय वाहनों से टोल वसूली को लेकर कांग्रेसियों का गुस्सा मंगलवार देर शाम फूट पड़ा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नेहरू नगर बाइपास रोड स्थित टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। कार्यकर्ताओं ने केबिन और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। साइन बोर्ड उखाड़कर फेंक दिया। इसके चलते दुर्ग-नागपुर हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। करीब दो घंटे तक बवाल चलता रहा, लेकिन पुलिस खड़े होकर तमाशा देखती रही।

मनोज चंद्राकर के नेतृत्व में प्रदर्शन करने पहुंचे थे कांग्रेसी

जानकारी के मुताबिक, नेहरू नगर और अंजोरा के बीच नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर स्थानीय सीजी-07 पासिंग वाले वाहनों से भी वसूली की जा रही है। इसे लेकर स्थानीय लोगों का विरोध है। कुछ दिन पहले इसी बात को लेकर भिलाई शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर से कर्मचारियों का विवाद भी हुआ था। उन्होंने टोल का विरोध किया, जिसके बाद बात बढ़ती चली गई और मारपीट तक हो गई थी। मंगलवार शाम को मुकेश चंद्राकर के नेतृत्व में कांग्रेसी और स्थानीय लोग टोल के विरोध में धरना देने के लिए पहुंचे थे।

कर्मचारियों ने टैक्स को सही बताया तो भड़के लोग

भीड़ देखते हुए एएसपी शहर संजय ध्रुव भी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि धरना देने के दौरान कर्मचारियों ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि, जो टोल टैक्स ले रहे हैं, वह बिल्कुल ठीक है। हम टैक्स लेते रहेंगे। ये सुनते ही कांग्रेसी और भड़क गए। जमकर नारेबाजी करते हुए कांग्रेसियों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। टोल प्लाजा बैरीकेटिंग के लिए रखी गई सामग्री, साइन बोर्ड को उखाड़ कर फेंक दिया। सीसीटीवी कैमरा, केबिन के कांच तोड़ दिए। अग्नशमन यंत्र को उठाकर फेंक दिया।

पुलिस के सामने ही होती रही तोड़फोड़

यह सब पुलिस के सामने चलता रहा और वो खड़े होकर देखती रही। इस दौरान दोनों ही और गुजरने वाले छोटे से लेकर भारी वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। करीब दो घंटे से भी ज्यादा समय तक हंगामा और तोड़फोड़ चलती रही। हालांकि इसके बाद स्थानीय स्तर पर कुछ समय के लिए सीजी-07 पासिंग वाहनों को टोल फ्री कर दिया, लेकिन बुधवार सुबह से फिर उनसे टोल की वसूली की जा रही है। दूसरी ओर कांग्रेसियों ने टोल फ्री करने के लिए कंपनी को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया है।

रात में टैक्स फ्री, सुबह फिर वसूली

वहीं दुर्ग शहर एएसपी संजय ध्रुव ने बताया कि, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को समझाया गया है। टोल प्लाजा में कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है। आकलन के बाद ही वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इधर बाफना टोल प्लाजा के मैनेजर एच कुंभकार ने बताया कि पिछले एक महीने से स्थानीय लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ता स्थानीय वाहनों को टोल फ्री करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर लगातार नेशनल हाइवे के अधिकारी और जिला प्रशासन को अवगत कराया गया था। फिर से जानकारी दी जाएगी।

ईडी ने एसकेएस इस्पात एंड पावर की संपत्ति की अटैच

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रदेश के बड़े उद्योग समूह एसकेएस इस्पात के खिलाफ कार्यवाही करते हुए बैंक से धोखाधड़ी के मामले में कंपनी की 517.81 करोड़ की सम्पत्ति अटैच कर दी है। अटैच की गई संपत्तियों में भूमि, भवन, प्लांट और मशीनरी है।

ईडी ने जारी अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि बैंक धोखाधड़ी मामले के सिलसिले में भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी के रूप में मैसर्स एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड की 517.81 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। मेसर्स का 895.45 करोड़ रु. सेथर लिमिटेड ईडी ने तमिलनाडु के त्रिची स्थित बॉयलर निर्माण कंपनी सीथर लिमिटेड के खिलाफ सीबीआई, बीएसएफ सेल, बैंगलोर द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। सेथर लिमिटेड ने रु. की ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया। इंडियन बैंक, एसएएम शाखा, मदुरै के नेतृत्व वाले ऋणदाताओं के एक संघ से 895.45 करोड़। कंपनी के खाते 31.12.2012 को एनपीए में बदल गए और बाद में 2017 में एनसीएलटी, चेन्नई के समक्ष आईबीसी के तहत कार्यवाही शुरू की गई। पीएमएलए के तहत जांच 2019 में शुरू की गई थी। कंपनी के निदेशक के परिसरों और अचल संपत्ति और आभूषणों की तलाशी ली गई रु. 2022 में 9.08 करोड़ रुपये की कुर्की की गई, जिसकी बाद में निर्णायक प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई। आगे की जांच में भारी भरकम रुपये का पता चला। 565 करोड़ रुपये के अलावा बहीखाते से बाहर रखा गया था। निवेश की बिक्री पर हानि के रूप में 228 करोड़ बट्टे खाते में डाले गए।

एसकेएस पावर जेनरेशन (छग) लि. (एसकेएसपीजीसीएल) के ईपीसी अनुबंध को लगभग रु. सेथर लिमिटेड ने 3500 करोड़ रुपये की हेराफेरी की थी। तत्कालीन मूल कंपनी एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड के शेयरों में निवेश की आड़ में एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड को 228 करोड़ रुपये दिए गए (हालांकि, 12ब प्रति वर्ष की दर से मिलने वाले ब्याज को बही-खाते से बाहर रखा गया था)। यह पैसा 2016-17 तक व्यापार प्राप्य के रूप में दर्ज किया गया था, जब इसे बैकडेटेड/जाली समझौते बनाकर निवेश की बिक्री पर नुकसान के रूप में लिखा गया था। यह एनसीएलटी की कार्यवाही शुरू होने से सिर्फ 2 दिन पहले किया गया था, जिससे बड़े पैमाने पर आपराधिक साजिश का खुलासा हुआ।

इस प्रकार, सीथर लिमिटेड के निदेशक के सुब्बुराज ने एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड के सीएमडी अनिल गुप्ता के साथ आपराधिक इरादे से सीथर की पुस्तकों से 793 करोड़ रुपये की संपत्ति हड़पने की साजिश रची, जो दिवालिया हो गई, जिसके परिणामस्वरूप आईबीसी, 2016 के तहत परिसमापन हुआ। 793 करोड़ रुपये के अपराध की आय को छुपाने के लिए समझौतों और लेनदेन की एक जटिल योजना बनाई गई थी, जिसे मेसर्स एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड में सुरक्षित रूप से रखा गया था। एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड ने 793 करोड़ रुपये की अपराध की आय का उपयोग किया। अपने नियमित व्यावसायिक उद्देश्य के लिए करोड़।

इस प्रकार, भूमि, भवन के रूप में मेसर्स एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड की अचल व्यावसायिक संपत्ति। इसकी पुस्तकों में 517.81 करोड़ रुपये मूल्य की सड़क और रेलवे साइडिंग के साथ संयंत्र और मशीनरी पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से संलग्न हैं।

पहली बारिश में बह गया 16.40 करोड़ की लागत से बन रहा पुल

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में धमधा ब्लाक के संगनी घाट में बन रहा पुल पहली ही बारिश में बुधवार को बह गया। इस पुल का निर्माण 16.40 करोड़ की लागत से किया जा रहा था। शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ने पर स्थानीय लोग देखने के लिए गए थे। इसी दौरान पुल ताश के पत्तों की तरह नदी में समा गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि घटिया निर्माण के चलते पुल गिरा है। संगनी घाट पर 400 मीटर लंबा पुल सिल्ली और ननकट्टी को जोड़ने के लिया बनाया जा रहा है। इस संगनी घाट को त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर शिवनाथ नदी, आमनेर नदी और संगनी नाला एक साथ मिलते है। पुल का निर्माण कार्य 11 नंबर 2020 को शुरू हुआ था। 16 महीने यानी की 11 अप्रैल 2022 को इसकी निर्माण कार्य पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी काम जारी था। पुल निर्माण कंपनी अमर इंफ्रास्ट्रक्चर से अनुबंध हो रहा था।

पुल से जुड़े तथ्य- निर्माण का नाम - सगनी घाट सिल्ली मार्ग में शिवनाथ नदी उच्च स्तरीय पहुंच मार्ग। लागत - 11.96 करोड़। स्वीकृत राशि - 16.40 करोड़। अनुबंध - वित्तीय वर्ष 2020-21। अनुबंधक का नाम - अमर इंफ्रा इंस्ट्रक्चर। कार्य शुरू करने का समय - 11 नवंबर 2020। कार्य पूरा करने का समय - 11 अप्रैल 2022।

हाईकोर्ट के फैसले को राजेश मूणत सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती

■ **साइंस कॉलेज मैदान के बाहर चौपाटी निर्माण का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने खारिज की मूणत की याचिका**

रायपुर। राजधानी में साइंस कॉलेज मैदान के बाहर बन रहे यूथ हब, ग्रीन कोरीडोर एवं वेंडिंग जोन पर रोक लगाने की जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह याचिका पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने हाईकोर्ट में दायर की थी। याचिका में यह तर्क दिया था कि यूथ हब, ग्रीन कॉरीडोर डेव्हलपमेंट प्लान, 2011 (रिवाईज्ड प्लान, 2021) के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए कि यूथ हब, ग्रीन कॉरीडोर का काम मई 2023 में पूर्ण हो चुका है, इस आधार पर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।

रायपुर के एजुकेशन हब में चौपाटी निर्माण के संबंध में हाईकोर्ट से आए निर्णय के बाद पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा नगर निगम रायपुर और स्मार्ट सिटी कंपनी ने एजुकेशन हब में चौपाटी का निर्माण संबंध में हाईकोर्ट में गलत तथ्य प्रस्तुत करके कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास

किया है। हमारा अभी भी मानना है कि रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में नगर निगम चौपाटी बना रहा है, वह अवैध है। हम हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।

राजेश मूणत ने कहा साइंस कॉलेज ग्राउंड और रविशंकर यूनिवर्सिटी कैंपस एजुकेशन हब है। यहां चौपाटी बनाना अवैधानिक है। हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करके नगर निगम रायपुर और स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा पेश किये गए गलत तथ्यों को उजागर करेंगे। न्यायपालिका पर हमारी पूरी निष्ठा है। हमें उम्मीद है कि छात्र हित में चौपाटी के निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाएगी।

हाईकोर्ट में गलत तथ्य प्रस्तुत करने का आरोप

नगर निगम रायपुर और स्मार्ट सिटी कंपनी पर एजुकेशन हब में चौपाटी का निर्माण के संबंध में गलत तथ्य प्रस्तुत करने का आरोप भाजपा की ओर से लगाये जा रहे हैं। उच्च न्यायालय ने इसी के आधार पर फैसला सुनाया है। जिस दिन एजुकेशन हब में चौपाटी का विरोध शुरू हुआ था, तब खेल एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नगर निगम रायपुर और स्मार्ट सिटी कंपनी को ज़मीन ट्रांसफर नहीं की गई थी। भाजपा का यह भी आरोप है कि नगर निगम रायपुर और स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा कोर्ट में कहा गया है कि चौपाटी का निर्माण पूर्ण ही चुका है। जबकि जनता के साथ 6 महीने से अवैध चौपाटी के लड़ाई जारी है। इस दौरान भी राज्य सरकार ने अपनी हठधर्मिता को प्रदर्शित करते हुए चौपाटी का निर्माण जारी रखा, जो कि नियम खिलाफ है।

राजेश मूणत ने कहा मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं कि छत्तीसगढ़ के युवा साथियों के लिए बनाये गए एजुकेशन हब में अवैध चौपाटी निर्माण के विरोध से कभी पीछे नहीं हटूंगा। भूपेश बघेल सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जहां तक लड़ाई लड़नी होगी, जरूर लड़ूंगा।

एजुकेशन हब में चौपाटी निर्माण के खिलाफ भाजपा

साइंस कॉलेज मैदान के सामने बन रहे एजुकेशन हब में चौपाटी निर्माण का भाजपा ने विरोध किया है। भाजपा ने पूर्व मंत्री राजेश मूणत के नेतृत्व में जनवरी महीने में अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी। हालांकि आंदोलन के 11 दिन बाद राजेश मूणत ने धरना स्थगित कर दिया था। रायपुर स्मार्ट सिटी एवं छत्तीसगढ़ शासन की ओर से हाईकोर्ट में इस मामले की पैरवी महाधिवक्ता सतीश चन्द वर्मा एवं अधिवक्ता अनिमेश तिवारी द्वारा की गई।

भाजपा ने बनाया और संवारा नया राज्यः साव

कांग्रेस को छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया से प्रेम होता तो जनता के हक का पैसा न लुटती

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा ने 15 साल क्या किया, यह वे जानते हुए भी अनजान बनने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता तो जानती और मानती है कि आज भूपेश बघेल करीब पौने पांच साल से जिस छत्तीसगढ़ का शोषण और दोहन कर कांग्रेस का पेट पाल रहे हैं, वह भाजपा ने बनाया और संवारा है। जिस अटलनगर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, वह भाजपा की देन है। भाजपा ने राज्य को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। भाजपा ने छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का सम्मान दिया। दरअसल झूठ कांग्रेस के डीएनए में है, इसलिए भूपेश बघेल भी इससे अछूते नहीं रह सकते। वे हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी को सम्मान देने पर आक्षेप करते हुए यह भूल जाते हैं कि हम मुंह में छत्तीसगढ़ महतारी और दिल में सोनिया महतारी रखने वाले लोग नहीं हैं। हम छत्तीसगढ़ महतारी की संतान हैं। हमारे महान नेता अटलबिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ की भावना के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। इसका शिशु की तरह संवेदनशीलता के साथ पालन

पोषण किया। कांग्रेस ने तो बंटवारे में मिली सत्ता के पहले दिन से ही छत्तीसगढ़ का शोषण शुरू कर दिया था। उस सरकार में भूपेश बघेल भी मंत्री थे। उन्हें तानाशाही का वह दौर तो याद होगा, जब कांग्रेस राज में प्रदेश की जनता दहशत में रहती थी। भूपेश बघेल किस संस्कृति की बात करते हैं। श्री साव ने पूछा आज जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की जो गौरवशाली संस्कृति है, वह बरसो से है छत्तीसगढ़ महतारी का नाम केवल राजनीतिक लाभ के लिए रटना छत्तीसगढ़ महतारी का सम्मान करना नहीं है। कांग्रेस के नेता तो सोनिया गांधी को राष्ट्र माता और राहुल गांधी को आज का महात्मा गांधी कहने से नहीं चूकते। भूपेश बघेल बताएं कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ राज्य क्यों नहीं बनाया। कांग्रेस के नेताओ ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का विरोध क्यों किया था। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के लिए कौन सा आंदोलन किया?

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद भेजने का अवसर जब मिला तो छत्तीसगढ़ महतारी बिसरा गई और सोनिया महतारी के आदेश पर शीर्षासन करते रहे। भूपेश बघेल बताएं कि केटीएस तुलसी, राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन को राज्यसभा भेजते समय छत्तीसगढ़ महतारी की आन, उसकी संतान याद क्यों नहीं आई। सोनिया की शान में छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान गिरवी क्यों रखा? उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए छत्तीसगढ़ महतारी का जाप किसी कालनेमि की तरह कर रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी और उसकी संतानों को धोखा दिया है। छत्तीसगढ़ को लूटकर सोनिया महतारी की सेवा में लगे हैं। अब जनता का सामना नहीं कर पा रहे तो छत्तीसगढ़ महतारी को राजनीति का मोहरा बनाने का घोर अनैतिक कार्य कर रहे हैं। महतारी पर भी कब्जेदारी! यह छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। छत्तीसगढ़ महतारी हर छत्तीसगढ़िया की महतारी है। महतारी का आशीर्वाद उसे मिलता है जो अपनी महतारी का मान रखता है। भूपेश बघेल सहित सारे कांग्रेसी तो सोनिया महतारी की चरण वंदना कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार एटीएम की तरह काम कर रही, इसलिए जाना पड़ता है दिल्लीः साव

बिलासपु। दिल्ली में बुधवार को हुई छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बैठक को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि, लगातार यह बात आती रहती है कि छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस के एटीएम के रूप में काम कर रही है। एटीएम के रूप में काम करने के लिए ही उन्हें बार-बार दिल्ली जाना पड़ता है। साव ने कहा कि, छत्तीसगढ़ की जनता भी इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। पिछले साढ़े चार सालों में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है। देश में छत्तीसगढ़ को शर्मसार किया है।

बिलासपुर पहुंचे भाजपा अध्यक्ष साव ने कहा कि, घोटाले का प्रदेश, ठप विकास, नशे और माफिया के गढ़ के रूप में छत्तीसगढ़ को देखा जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ में कुछ चल रहा है तो केवल लूट खसोट और घोटाला चल रहा है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। सरकार ने छत्तीसगढ़ की आज ये हालत कर दी है। जनता ने तय कर लिया है कि सरकार की विदाई करना है। राज्य में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश है। साढ़े चार साल में सिर्फ लोगों को ठगने और धोखा देने का काम किया है।

साव ने कहा कि, एक बार फिर झूठे वादे और लुभावने वादे करने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता एक बार धोखा खा चुकी है। एक भी वादे राज्य सरकार ने पूरे नहीं किए हैं। सरकार ने आज छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है। विकास के सारे काम ठप हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस की विदाई करने का तय कर लिया है। नवंबर में छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी।

विश्व हम पर कर रहा है गर्वः डॉ. रमन

■ पीएम मोदी को जाता है देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने का श्रेय

राजनांदगांव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे संपर्क से समर्थन अभियान के तहत आज पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने राजनांदगांव के गायत्री विद्यापीठ में शिक्षाविदों से चर्चा की और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी शराबबंदी को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने दिया बयान।

इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। आज पूरा विश्व हम पर गर्व कर रहा है। डॉ रमन सिंह ने शिक्षाविदों को केंद्र सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। वहीं प्रदेश में शराबबंदी के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार शराबबंदी की ओर बढ़ रही थी, प्रदेश में भाजपा सरकार बनते ही हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं जिसको लेकर लगातार राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। लगातार भाजपा बैठक लेकर तैयारियों में जुट गई है वहीं आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह राजनांदगांव पहुंचे और यहां आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की।

छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन की प्रगति को भारत सरकार ने सराहा

■ 25 लाख से अधिक परिवारों में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान कर छत्तीसगढ़ ने 50 फीसद से अधिक का लक्ष्य पूरा किया

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन की उल्लेखनीय प्रगति की भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने सराहना की है। जल शक्ति मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य में 25 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने की सराहना करते हुए बधाई और शुभकामनाएं दी है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने जल जीवन मिशन का 50 प्रतिशत से अधिक का लक्ष्य पूरा होने पर प्रसन्नता जताते हुए जल जीवन

मिशन के क्रियान्वयन में जुटे अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ लक्षित ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का काम तेजी से किया जा रहा है। बीते एक पखवाड़े में एक लाख 27 हजार से अधिक परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किया जाना इस बात का प्रमाण है। आगामी दिनों में मिशन के कामों में और तेजी लायी जाएगी।

गौरतलब है कि जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में 25 लाख 11 हजार 850 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है जो कि घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने के लक्ष्य का 50.13 प्रतिशत है। अब तक छत्तीसगढ़ राज्य के 556 गांवों के शत-प्रतिशत परिवारों को भी घरेलू नल कनेक्शन दिया जा चुका है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत कुल 50 लाख 10 हजार 499 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल प्रदाय किए जाने का लक्ष्य है।

प्रदेश प्रभारी डॉ. चंदन यादव का दौरा कार्यक्रम

रायपुर । एआईसीसी के सचिव एवं प्रदेश प्रभारी डॉ. चंदन यादव 29 जून गुरूवार को सुबह 9 बजे रायपुर से ग्राम खैरबना विधानसभा क्षेत्र डोंगरगांव, राजनांदगांव के लिये रवाना होंगे। 11 बजे ग्राम खैरबना पहुंचकर बूथ चलो अभियान में शामिल होंगे। 11.30 बजे ग्राम खैरबना से टाटेकसा के लिये रवाना होंगे। दोपहर 12 बजे ग्राम टाटेकसा पहुंचकर बूथ चलो अभियान में शामिल होंगे। दोपहर 12.30 बजे ग्राम टाटेकसा से सीताकोटा के लिये रवाना होंगे। दोपहर 1 बजे सीताकोटा पहुंचकर बूथ चलो अभियान में शामिल होंगे। दोपहर 1.30 बजे ग्राम सीताकोटा से रंगकठेरा के लिये रवाना होंगे। दोपहर 2 बजे ग्राम रंगकठेरा पहुंचकर बूथ चलो अभियान में शामिल होंगे। दोपहर 2.30 बजे ग्राम रंगकठेरा से माथलडबरी के लिये रवाना होंगे। दोपहर 3 बजे ग्राम माथलडबरी पहुंचकर बूथ चलो अभियान में शामिल होंगे। दोपहर 3.30 बजे माथलडबरी से मोहड़ के लिये रवाना होंगे। शाम 4 बजे मोहड़ पहुंचकर बूथ चलो अभियान में शामिल होंगे। शाम 4.30 बजे मोहड़ से रायपुर के लिये रवाना होंगे।

बीजेपी का लाभार्थी सम्मेलन आज

रायपुर। बीजेपी गुरुवार को रायपुर में लाभार्थी सम्मेलन करेगी. लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में होगा.इस आयोजन की जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि इस लाभार्थी सम्मेलन में मोदी सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों को बुलाया गया है। सम्मेलन में पूर्व सीएम रमन सिंह, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी के साथ ही शहर के अन्य भाजपा नेता मौजूद रहेंगे। मूणत ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल के दौरान देश की जनता के लिए कई हितकारी योजनाओं की शुरुआत की। जनता ने भी इन योजनाओ से जुड़कर उन्हें सफल बनाकर राष्ट्रनिर्माण की दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में 29 जून को दोपहर 3 बजे से कार्यक्रम का आयोजन होगा।

लाभार्थी सम्मेलन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी इन्ही लाभार्थियों का सम्मान करेगी। मूणत ने जानकारी दी कि गुरुवार को आयोजित लाभार्थी सम्मलेन में केंद्र सरकार की योजनाओ का लाभ लेने वाले जागरूक नागरिको को बड़ी संख्या में आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि बीजेपी अपने महासम्पर्क अभियान के माध्यम से मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक ले जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओ के सीधा संवाद करके उनमे जोश भरने का काम किया है। भाजपा के कार्यकर्ता आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हो चुके है।

बीजेपी अपने अभियान में जुटी हुई है,जिसके तहत पूर्व में गृहमंत्री अमित शाह दुर्ग प्रवास पर थे,जबकि 30 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर आ रहे है। इसके लिए बीजेपी की तैयारी चल रही है। बिलासपुर के रेलवे ग्राउंड पर जेपी नड्डा आम सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस सामाजिक न्याय की बात ना करे तो ही ठीक साथ ही कांग्रेस की दिल्ली में मीटिंग और सामाजिक न्याय पर जोर के सवाल पर मूणत ने कहा कि कांग्रेस सामाजिक न्याय कि बात नहीं ही करे तो ठीक है क्योंकि न्याय न आदिवासी वर्ग के साथ हुआ, न श्रमिकों के साथ, न बुजुर्गों के साथ और न ही महिलाओं के साथ हुआ।

प्रमुख समाचार छत्तीसगढ़/राजधानी

मोदी सरकार महंगाई कम करने में नाकामः मरकाम

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार 100 दिनों में महंगाई कम करने के वायदे का 9 साल में पूरा नहीं कर पाई, महंगाई तो कम हुए नहीं बल्कि 9 साल में जनता महंगाई के बोझ के तले दब गई, रोजी

रोजगार छीने गए, लोगों के घरों में खाद्य सामग्रियों की कमी दिख रही है ऐसा प्रतीत होता है कि आधा पेट भर कर लोग जीवन जीने मजबूर हैं महंगाई के चलते बच्चों को सुपोषित आहार नहीं मिल पा रहा है हर वर्ग पर मोदी के महंगाई का प्रभाव दिख रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा ने कहा कि देश में राहर दाल, खाद्य तेल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी से जनता का जीवन दूभर हो गया है। टमाटर के दाम 100 रू. और राहर दाल 150 रू. में आम आदमी खरीदने को मजबूर है। साल भर के भीतर ही दूध, तेल, नमक जैसे जरूरी चीजों की कीमत में 24 प्रतिशत तक का इजाफा हो गया है। साल भर पहले जो चावल 35.27 रुपये किलो था आज 60 रुपए किलो हो चुका है, गेहूं 27 रुपए से बढ़ कर 42 रुपए किलो, अरहर दाल 90 रुपये से बढ़कर 150 रुपये किलो, दूध 49 रुपये से बढ़कर 55 रुपये और वनस्पति तेल 136 रुपये से बढ़कर 143 रुपये हो गया है। 9 साल पहले अच्छे दिन का जो वादा किया गया था वह महंगे दिन बन चुका है। अब जनता मोदी सरकार द्वारा की जा रही बेतहाशा वसूली से त्रस्त हो चुकी है।

भाजपा कार्यकर्ता भी ठगा महसूस कर रहे हैंः वर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती असमानता से जूझ रहे आम जनता के साथ ही भाजपा के कार्यकर्ता भी मोदी राज के 9 वर्ष में अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। ना नौकरी है,

ना रोजगार, महंगाई ऐतिहासिक रूप से शिखर पर है, गरीबी और भुखमरी दिनोंदिन बढ़ रही है अच्छे दिन की आस तो अब अंधभक्तों की भी टूटने लगी है। मोदी राज में केंद्र की सत्ता और देश के संसाधन केवल चंद पूंजीपतियों के लाभ के लिए ही समर्पित है। भाजपा के कार्यकर्ताओं के जिम्में तो बस मन की बात सुनो, फोटो अपलोड करो और सोशल मीडिया में झूठी उपलब्धि के कंटेंट प्रसारित करते रहो, खबरदार जो किसी तरह के अधिकारों की बात कही तो देशद्रोही करार दिए जाओगे। पहले तो केवल मोदी जी के मन की बात सुनकर फोटो अपलोड करना पड़ता था अब तो भाजपा कार्यकर्ता इस बात से व्यथित है कि नड्डा जी के कार्यक्रम के सार्वजनिक प्रसारण का वीडियो/फ़ोटो भी अपलोड करने कहा जा रहा है। भाजपा के ही कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर भी नाराजगी हैं कि पहले तो केंद्रीय विद्यालयों में स्थानीय सांसदों का कोटा हुआ करता था जिसके चलते छोटे कार्यकर्ताओं के परिजनों का भी केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश हो पाता था अब तो मोदी सरकार ने वह भी खत्म कर दिया है। रोज़गार के अवसर लगातार घट रहे हैं।

राजेश मूणत चौपाटी के मामले में नफरत और वैमनस्यता की राजनीति कर रहे थेः ठाकुर

रायपुर। चौपाटी एवं जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के विषय पर भाजपा नेता राजेश मूणत एवं देवजी भाई पटेल के द्वारा न्यायालय में लगाई गई याचिका खारिज होने पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता

धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व मंत्री एवं प्रवक्ता राजेश मूणत को यूथ हब, ग्रीन कॉरिडोर, वेंडिंग जोन मामले में न्यायालय में मुंह की खानी पड़ी है। राजेश मूणत यूथ हब को चौपाटी बताकर दुष्प्रचार कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे, यूथ हब को चौपाटी बताकर विरोध की आड़ में नफरत और वैमनस्यता की राजनीति करने का षड्यंत्र रच रहे थे। दुर्भावना फैला रहे थे। जिसे पहले जनता ने खारिज किया, अब न्यायालय में भी याचिका खारिज कर दी है और राजेश मूणत को आईना दिखाया है। जिस वक्त राजेश मूणत यूथ हब को चौपाटी बताकर विरोध में आमरण अनशन पर बैठे थे उसी दौरान भाजपा के नेता दबे जुबान पर इसे राजेश मूणत की नासमझी बता रहे थे और उसके आंदोलन से कन्नी काट रहे थे, कुछ दिन धरना देने के बाद राजेश मूणत अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के हाथों जूस पीकर अनशन को समाप्त किया था।

मरकाम अपने तानाशाह का मुकाबला कर आदिवासी पुरुषार्थ का परिचय देंः चंदेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम से

कहा है कि वे देश के प्रधानमंत्री पर बेहूदा बयानबाजी करने की बजाय प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तानाशाही का मुकाबला कर आदिवासी पुरुषार्थ का परिचय दें। तानाशाह और भ्रष्टाचार के प्रतीक भूपेश बघेल और हिटलर की मौसी बनीं सैलजा के सामने मरकाम का हथियार डाल देना सही नहीं है। उन्हें ऐसे ऊल जुलूल बयान देकर कुछ भी हासिल नहीं होगा। सैलजा और बघेल उन्हें बस नाम का मुखिया बनाये रखेंगे और ऐसे ओछे बयान देने के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। मरकाम को इससे बचना चाहिये और आदिवासी अस्मिता के लिए इन दोनों से लड़ना चाहिये। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि भूपेश बघेल की एक डांट फटकार पर सहम जाने वाले मरकाम, अपने फैसलों को सैलजा द्वारा रद्दी कागज बना देने पर डर जाने वाले मरकाम उस शख्सियत को डरा सहमा बता रहे हैं, जिसके सामने सारी दुनिया सम्मान से सिर झुकाती है और जिसकी लोकप्रियता से घबराकर राजनीति के तमाम सांप, छछूंदर, चूहे, बिल्ली, बंदर, भालू, सियार, लड़इये एक घाट पर फोटो खिंचवा रहे हैं। डरा हुआ कौन है, सहमा हुआ कौन है।

पहली किस्त ही किसानों तक नहीं पहुंची हैः संदीप शर्मा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा है कि किसानों के धान भुगतान के नाम पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के तमाम दावों का गड़बड़ी भी अब सामने आ रही है। श्री शर्मा ने कहा कि किसानों को धान के बकाया भुगतान की पहली किश्त की राशि जारी किए जाने के दावे की सच्चाई यह है कि एक माह से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी हजारों किसानों के खाते में एक रुपया तक नहीं आया है! भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक तरफ किसानों को धान के अधिकतम दाम देने का ढोल पीट रहे हैं जबकि दूसरी तरफ परेशान किसान अब बैंक और कृषि कार्यालयों के चक्कर काटने के लिए विवश हो रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि राशि जारी नहीं होने के कारण किसानों का कृषि-कार्य ठप्प पड़ गया है। हमने जून के पहले सप्ताह में ही कबीरधाम जिले के लगभग 51 हजार किसानों के इस राशि से पूरी तरह वंचित होने का मामला सामने लाकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था, लेकिन प्रदेश सरकार की लापरवाही के चलते किसानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। अब जबकि बारिश शुरू हो चुकी है, किसानों को जुताई-बुआई और बीज-खाद के लिए पैसों की सख्त जरूरत है, तब यह खुलासा हो रहा है कि ऐसे मामले पूरे प्रदेशभर में हैं और ऐसा लग रहा है कि बकाया भुगतान की पहली किश्त की राशि से वंचित किसानों की यह संख्या लाखों में है।

नया भारत उत्सव का आयोजन एनआईटी रायपुर में सम्पन्न

■ सांसद सुनील सोनी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में पढ़ने वाले युवाओं से किया संवाद

रायपुर। केंद्र सरकार को 9 साल पुरे होने के उपलक्ष्य में नया भारत उत्सव के अंतर्गत युवा संवाद कार्यक्रम में आज रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मे (एनआईटी) पढ़ने वाले छात्र युवाओं से संवाद किया । इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथी के तौरपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छत्तीसगड प्रमुख डॉ. पुर्णेदु सक्सेना, शिक्षा विद डॉ. जवाहर सेट्टी और एनआईटी संस्था के प्रभारी निदेशक डॉ. आर. के. त्रिपाठी मौजूद थे।

इस युवा संवाद कार्यक्रममें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था मे पढ़नेवाले युवाओं ने

सांसद सोनी से केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाएँ, कार्यक्रम, नितियां और उपलब्धियों के बारे में कई सवाल किये। जिसके जबाब उन्होंने दिये ।

देश के विदेश नीति के बारे में छात्रो द्वारा पुछे गये सवाल पर जवाब देते हुए सांसद सोनी ने भारत की प्रतिष्ठा विदेशों मे बढ़ गयी है, और अमरिका जैसे महासत्ता भी भारत का महत्त्व जान गयी है। पिछले नौ साल में केंद्र सरकारने स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन- हर घर नल जैसी योजनाओं के माध्यमसे देश के ग्रामीण क्षेत्रमें आमुलाग्र परिवर्तन किया है । अबतक 9 करोड परिवारोंके घरोंमें नल द्वारा पिने का पानी मुहैया किया जा रहा है और अगले 2024 के अंत तक देश के सभी घरोंमें नल द्वारा पानी देने का लक्ष्य है । उन्होंने बताया की, बिमार होने पर पाच लाख रुपयोंतक मुफ्त इलाज करने का प्रावधानवाली आयुष्यमान भारत जैसे स्वास्थ्य योजनाने आम आदमी के जीवन में सुखभरे दिन लाये है। उज्जवला योजना के कारण पैसेवालों के घरमें दिखनेवाला रसोई चुल्हा और गॅस अब घर- घर पहुंच गया है।

असौंदा में शराब कोचिये हावी, राहगीरों सहित ग्रामीण त्रस्त

■ मोर्चा खोलने की तैयारी

रायपुर। अमेरी से माठ सड़क मार्ग पर स्थित ग्राम असौंदा में शराब कोचिये हावी हो चले हैं। इस मुख्य सड़क मार्ग पर धड़ल्ले से अवैध शराब बिकने से न केवल इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीर वरन् ग्राम के आम ग्रामीण भी त्रस्त हो चले हैं । ध्यानाकर्षण के बाद भी आबकारी व खरोरा थाना अमला द्वारा ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा इसके खिलाफ प्रभावित आसपास के ग्रामों के ग्रामीणों के सहयोग से मोर्चा खोलने व इस हेतु रणनीति बनाने शीध्र ही बैठक बुलाने की तैय्यारी की जा रही है। ज्ञातव्य हो कि मंदिर हसौद-कोसरंगी सड़क मार्ग को रायपुर-खरोरा सड़क मार्ग से जोड़ता है अमेरी-माठ सड़क मार्ग। इसकी वजह से रात-दिन इस मार्ग पर राहगीरों का आवाजाही लगा रहता है। इस मार्ग पर स्थित ग्राम असौंदा में सड़क किनारे ही 8 - 10 कोचिये धड़ल्ले से शराब बेचते हैं जिसकी वजह से राहगीरों को भी अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ता है। लगभग 7-8 माह पूर्व शराब की वजह से ग्रामों का माहौल अशांत होने की? स्थिति को देखते हुये क्षेत्रीय ग्रामीणों की पहल पर शराब विरोधी मुहिम में सक्रिय

किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा ने मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के ग्राम टेकारी में 15 -20 ग्रामों के ग्राम प्रमुखों व पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक आहूत की थी जिसमें असौंदा के पंचायत प्रतिनिधि भी शामिल थे। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के ग्राम कठिया में चल रहे अधोषित भट्ठी को यहां के ग्रामीणों ने आसपास के ग्रामों के ग्रामीणों व मंदिर हसौद थाना प्रभारी विरेन्द्र चंद्रा सहित थाना अमला के सक्रिय सहयोग से बंद कराने में सफलता हासिल की है वहीं खरोरा थाना क्षेत्र के? अंतर्गत आने वाले ग्राम बुडेनी के ग्रामीणों ने मोर्चा खोल अवैध शराब बिक्री को बंद करा रखा है। श्री शर्मा ने बतलाया कि बैठक में शामिल रहे मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के? ग्राम बड़गांव, मुनगेसर, कुटेसर, सोनपैरी सहित खरोरा थाना क्षेत्र के ग्राम असौंदा सहित मुड़पार , खौली , भडहा , बुडगहन , फरहदा आदि में अब भी धड़ल्ले से अवैध शराब बिक्री जारी है। असौंदा से होकर आवाजाही करने वाले ग्रामो के ग्राम प्रमुखों के आग्रह व असौंदा के ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुये सरपंच राजेश साहू ने पंचायत प्रतिनिधियों सहित महिलाओं व ग्रामीणों के सहयोग से बैठक कर शीध्र ही मोर्चा खोलने की जानकारी दी है ।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.